

प्रधानमंत्री कार्यालय

बाड़मेर में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य की शुरुआत के अवसर पर एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 16 JAN 2018 6:07PM by PIB Delhi

विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयो और बहनों, खम्मा घणी, नमस्कार।

दो दिन पहले ही हिन्दुस्तान के हर कोने में मकर सक्रांति का पर्व मनाया गया और मकर सक्रांति के बाद एक प्रकार से उत्क्रांति का संकेत जुड़ा हुआ होता है। सक्रांत के बाद उन्नति अन्तर्निहित होती है। मकर सक्रांति के पर्व के बाद राजस्थान की धरती पर पूरे हिन्दुस्तान को ऊर्जावान बनाने का एक अहम प्रयास, एक अहम initiative, एक अहम प्रकल्प; उसका आज कार्य आरंभ हो रहा है।

मैं वसुंधरा जी का और धर्मेन्द्र प्रधान जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्य आरंभ करने का कार्यक्रम बनाया और इसके कारण आने वाले दिनों में कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो- जब पत्थर जड़ेगा तो लोग पूछेंगे पत्थर तो जड़ दिया कार्य आरंभ की date तो बताओ। और इसलिए इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश में एक जागरूकता आएगी कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। जब कार्य आरंभ होता है तब सामान्य मानवी को विश्वास होता है।

मुझे खुशी है इस पूरे क्षेत्र की विकास यात्रा में शरीक हो करके ये कार्य आरंभ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब मुझे पूरे project की detail दे रहे थे अफसर, सारी बारीकियां बता रहे थे अभी। सब कुछ बता दिया उन्होंने, उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी को हमने सारी जानकारी दे दी है, तो मैंने उनको पूछा उद्घाटन की तारीख बताइए और मुझे विश्वास दिया गया है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा 2022. भारत के वीरों ने, आजादी के सेनानियों ने; किसी ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी, किसी ने फांसी के तख्त पर चढ़ करके वंदे मातरम के नाद को ताकतवर बनाया, आजाद हिन्दुस्तान, भव्य भारत, दिव्य भारत, इसका सपना देखा- देश आजाद हुआ। 2022 में आजादी के 75 साल हो जाएंगे। ये हम सबका दायित्व है, हर हिन्दुस्तानी का दायित्व है, 125 करोड़ नागरिकों का दायित्व है कि हम 2022 में जो सपने आजादी के दीवानों ने देखे थे, वैसा हिन्दुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करें।

ये समय संकल्प से सिद्धि का समय है। आज यहां पर आपने संकल्प लिया है कि 2022 तक इस रिफाइनरी का कार्य आरंभ कर देंगे। मुझे विश्वास है ये संकल्प सिद्धि बन करके रहेगा और जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा तब यहां से देश को नई ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मैं राजस्थान सरकार को, श्रीमान धर्मेन्द्र जी के विभाग को, भारत सरकार के प्रयासों को और आप सभी मेरे राजस्थान के भाइयो, बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।

बाड़मेर की ये धरती, ये वो धरती है जहां रावल मल्लीनाथ, संत तुलसा राम, माता रानी फटियानी, नागनेकी माता, संत ईश्वरदास, संत धारूजी मेग, न जाने कितने अनगिनत सात्विक संत जगत के आशीर्वाद से पली-बढ़ी ये बाड़मेर की धरती। मैं आज उस धरती को नमन करता हूँ।

पंचपद्रा की ये धरती स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय गुलाबचंद जी, सालेचा की कर्मभूमि, गांधीजी के नमक सत्याग्रह के पहले- उन्होंने यहां पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।

इस क्षेत्र में पीने का पानी लाने में, ट्रेन लाने में, पहला कॉलेज खोलने में गुलाबचंद जी को हर कोई याद करता है। मैं पंचपद्रा के इस सपूत को भी प्रणाम करता हूं।

भाइयो, बहनों, मैं आज इस धरती पर भैरोसिंह शेखावत जी को भी याद करना चाहता हूं। आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए, संकटों से मुक्त राजस्थान बनाने के लिए और इस बाड़मेर में इस रिफाइनरी की सबसे पहले कल्पना करने वाले भैरोसिंह शेखावत जी को भी मैं आज स्मरण करता हूं।

आज मैं जब बाड़मेर की धरती पर आया हूं तो यहां उपस्थित सबसे मैं आग्रह करता हूं कि हम सब अपने-अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करें कि इसी धरती के सपूत श्रीमान जसवंत सिंह जी, उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए और उनके अनुभव का लाभ देश को मिले। हम सब उनके उत्तम स्वास्थ्य और जल्दी स्वस्थ हो करके हमारे बीच आएँ, ऐसी प्रार्थना हम सब करें, और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा।

भाइयो, बहनों, दुर्भाग्य से हमारे देश में इतिहास को भुला देने की परम्परा रही। वीरों को, उनके त्याग और बलिदान को हर पीढ़ी को मान-सम्मान के साथ स्मरण करके नया इतिहास बनाने की प्रेरणा मिलती है और वो लेते रहना चाहिए।

आपने देखा होगा इसरायल के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। 14 साल के बाद वे यहां आए हैं। और देश आजाद होने के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इसरायल की धरती पर गया था। और मेरे देशवासी, मेरे राजस्थान के वीरो, आपको गर्व होगा कि मैं इसरायल गया, समय की खींचातानी के बीच भी मैं हायफा गया और वहां जा करके प्रथम विश्वयुद्ध में हायफा को मुक्त कराने के लिए आज से 100 साल पहले जिन वीरों ने बलिदान दिया था उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने गया था। और उसमें नेतृत्व किया था इसी धरती की वीर संतान मेजर दलपत सिंह जी ने। मेजर दलपत सिंह शेखावत- 100 साल पहले इसरायल की धरती पर प्रथम विश्वयुद्ध का नेतृत्व करते हुए हायफा को मुक्त किया था।

दिल्ली में एक तीन मूर्ति चौक है। वहां तीन महापुरुषों की, वीरों की मूर्तियां हैं। इसरायल के प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान आते ही, हम दोनों सबसे पहले इस तीन मूर्ति चौक में गए। वो तीन मूर्ति चौक उस मेजर दलपत सिंह के बलिदान की याद में बना हुआ है और इस बार इसरायल के प्रधानमंत्री भी वहां नमन करने आए। हम दोनों वहां गए और उस तीन मूर्ति चौक का नाम तीन मूर्ति हायफा चौक रखा गया, ताकि इतिहास याद रहे, मेजर दलपत सिंह शेखावत याद रहे। मेरे राजस्थान की वीर परम्परा याद रहे। ये काम अभी दो दिन पहले करने का मुझे सौभाग्य मिला।

भाइयो, बहनों, ये वीरों की धरती है। बलिदानियों की धरती है। शायद बलिदान की कोई इतिहास की घटना ऐसी नहीं होगी कि जिसमें मेरी इस वीर धरती के महापुरुषों का रक्त से उसको अभिषिक्त न हुई हो। और मैं ऐसे सभी वीरों को आज यहां प्रणाम करता हूं।

भाइयो, बहनों- राजस्थान में तो मैं पहले बहुत आता था। संगठन का काम करने के लिए आता था, पड़ोस का मुख्यमंत्री रहा उसके कारण आता रहता था। इस इलाके में भी कई बार आया हूं। और हर बार एक बात सामान्य मानवी के मुंह से सुनता रहता था कि राजस्थान में कांग्रेस और अकाल, ये जुड़वां भाई हैं। जहां कांग्रेस जाएगी, वहां अकाल साथ-साथ जाता है। और वसुंधरा जी के भाग्य में लिखा हुआ है जब भी उनको सेवा करने का मौका मिला, इस सूखी धरती को पानी मिलता रहा।

भाइयो, बहनों- लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है। राजस्थान को आगे लेके जाना है। राजस्थान के विकास की यात्रा को देश के विकास में एक नई ताकत देने वाला राजस्थान है और वो राजस्थान की धरती पर करके दिखाना है।

भाइयो, बहनों हमारे धर्मन्द् जी शिकायत कर रहे थे, वसुंधरा जी शिकायत कर रही थीं; उनकी शिकायत सही है। लेकिन ये सिर्फ बाइमेर की रिफाइनरी में ही हुआ है क्या? क्या पत्थर सिर्फ यहीं पर जड़कर फोटो खिंचवाई गई है क्या? क्या पत्थर यहीं पर लगा करके लोगों की आंखों में धूल झाँकी गई है क्या? जो लोग जरा रिसर्च करने के आदी हैं। बाल की खाल उधेड़ने की जो ताकत रखते हैं; मैं ऐसे हर किसी को निमंत्रण देता हूँ कि जरा देखो तो सही कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली कैसी रही थी। बड़ी-बड़ी बातें करना, जनता-जनार्दन को गुमराह करना, ये कोई सिर्फ बाइमेर की रिफाइनरी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है; ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है, उनके स्वभाव का हिस्सा है।

जब मैं प्रधानमंत्री बना, बजट देख रहा था, और मैं रेलवे बजट देख रहा था। तो मेरा जरा स्वभाव है, मैंने पूछा कि भाई ये रेलवे बजट मैं हम इतनी-इतनी घोषणाएं करते हैं, जरा बताओ तो पीछे क्या हुआ है। आप चौंक जाएंगे भाइयो-बहनों, आपको सदमा पहुंचेगा। भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है। वहां देश को गुमराह करने का हक नहीं होता है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, कई सरकारें आईं और गईं- रेलवे बजट में 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा ऐसी-ऐसी योजनाओं की घोषणाएं की गईं- जो आज उसका नामोनिशान नहीं है, वैसे ही कागज पर लटकी पड़ी हैं।

हम आए, हमने फैसला किया कि कुछ पल की तालियां पाने के लिए संसद में जो सदस्य बैठे हैं, वो अपने इलाके में कोई रेल का प्रोजेक्ट आ जाए तो ताली बजा दें और रेलमंत्री खुश हो जाएं, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। यही सिलसिला चला, हमने आ करके कह दिया कि रेल बजट में ये वाहवाही लूटना और झूठी तालियां बजवाने का कार्यक्रम बंद। जितना होना तय है इतना ही बताइए। एक दिन आलोचना होगी लेकिन देश को धीरे-धीरे सही बोलने की, सही करने की ताकत आएगी, और ये काम हम करना चाहते हैं।

इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए One rank one pension, मेरे फौज के लोग यहां बैठे हुए हैं। फौजियों के परिवारजन यहां बैठे हुए हैं। 40 साल One rank one pension, इसकी मांग नहीं उठी थी। क्या फौज के लोगों को बारी-बारी से वादे नहीं किए गए थे? हर चुनाव के पहले इसे भुनाने का प्रयास नहीं हुआ था? ये उनकी आदत है। 2014 में भी आपने देखा होगा, 5-50 निवृत्त फौज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और One rank one pension की बातें भुनानी, ये करते रहे हैं।

और बाद में जब चारों तरफ से दबाव पड़ा, और जब मैंने 15 सितंबर, 2013, रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों के सामने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, One rank one pension लागू करेगी। तब आनन-फानन में, अफरा-तफरी में जैसे ही यहां refinery का पत्थर जड़ दिया गया उन्होंने interim बजट में 500 करोड़ रुपया One rank one pension के नाम पर लिख दिया।

देखिए, देश के साथ इस प्रकार का धोखा करना, और फिर भुनाते रहे चुनाव में कि देखिए One rank one pension के लिए बजट में हमने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा चलो भाई One rank one pension लागू करो, हमने वादा किया है तो अफसर समय बिताते रहते थे। मैंने कहा, हुआ क्या है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आपको जान करके हैरानी होगी, बजट में 500 करोड़ लिखा गया था लेकिन दफ्तर के अंदर ये One rank one pension है क्या? ये One rank one pension की पात्रता किसकी है? उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा? आप हैरान होंगे- सिर्फ रिफाइनरी कागज पर थी, वहां तो One rank one pension, कागज पर भी नहीं था। न सूची थी, न योजना थी, सिर्फ चुनावी वादा।

भाइयो, बहनों, उस काम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कागज पर चीजें इकट्ठी करते-करते मुझे डेढ़ साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था देश के लिए मरने-मिटने वाली फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। समेटते गए, समेटते गए, फिर हिसाब लगाया कितने पैसे लगेंगे।

भाइयो, बहनों, ये 500 करोड़ रुपया- तो मैंने सोचो शायद 1000 करोड़ होगा, 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा। जब हिसाब जोड़ने बैठा तो भाइयो-बहनों, वो मामला 12 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया। 12 हजार करोड़, अब कांग्रेस पार्टी One rank one pension 500 करोड़ रुपये में कर रही थी, क्या उसमें ईमानदारी थी क्या? क्या सच में फौजियों को कुछ देना चाहते थे क्या? क्या फौज के निवृत्त सेनानियों के प्रति ईमानदारी थी क्या? उस समय के वित्तमंत्री इतने तो कच्चे नहीं थे। लेकिन 500 करोड़ रुपये का टीका लगा करके जब यहां पत्थर जड़ दिया, वहां पर बजट में लिख दिया और हाथ ऊपर कर दिए।

भाइयो-बहनों, हमें करीब 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बोझ आया तो मैंने फौज के लोगों को बुलाया। मैंने कहा- भाई मैंने वादा किया है, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12 हजार करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ रुपये की बात करके चले गए, मेरे लिए 12 हजार करोड़ रुपये निकालना ईमानदारी से निकालना है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए।

फौज के लोगों ने मुझे कहा- प्रधानमंत्री जी आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता भाई- आपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। लेकिन मेरी मदद कीजिए। मैं एक साथ 12 हजार करोड़ रुपया नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे देना है तो देश के गरीबों की कई योजनाओं से निकालना पड़ेगा। गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा।

तो मैंने कहा कि मेरी एक request है- क्या मैं इन्हें चार टुकड़ों में दूं तो चलेगा? मेरे देश के वीर सैनिक 40 साल से जिस One rank one pension को पाने के लिए तरस रहे थे, लड़ रहे थे; देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो प्रतिबद्ध था, वे चाहते तो कह देते कि मोदीजी सब सरकारों ने हमें ठगा है। हम अब इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। आपको देना है तो अभी दे दो वरना आपका रास्ता आपको मंजूर, हमारा रास्ता हमें मंजूर- कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मेरा देश का फौजी Uniform उतारने के बाद भी तन से, मन से, हृदय से फौजी होता है। देशहित जीवन के अंतकाल तक उसकी रंगों में होता है। और एक पल के बिना, एक पल को बिताए बिना मेरे फौज के भाइयों ने कह दिया- प्रधानमंत्री जी आपकी बात पर हमें भरोसा है। भले चार टुकड़े करने पड़ें, छह करने पड़ें, आप अपनी फुरसत से कीजिए, बस एक बार निर्णय कर लीजिए। हम- जो भी निर्णय करेंगे मान लेंगे।

भाइयो-बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक चार किस्त दे चुका हूं। 10 हजार 700 करोड़ रुपये उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाली है। और इसलिए सिर्फ पत्थर जड़ना ही नहीं, ये देश में ऐसी सरकारें चलाना, ये इनकी आदत हो गई है।

आप मुझे बताइए- गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ- चार दशक से सुनते आए हो कि नहीं आए हो? गरीबों के नाम पर चुनावों के खेल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लेकिन क्या कोई गरीब की भलाई के लिए योजना नजर आती है? कहीं नजर नहीं आएगी। आजादी के 70 साल के बाद भी वो यही कहेंगे, जाओ गड़वा खोदो और शाम को कुछ ले जाओ और दाना-पानी कर लो। अगर अच्छी तरह देश के विकास की चिंता की होती तो मेरे देश का गरीब खुद गरीबी को परास्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया होता।

हमारी कोशिश है empowerment of poor-गरीबों का सशक्तिकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुले। इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर किया गया लेकिन बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया।

आजादी के 70 साल बाद जब हम आए, हमने निर्णय किया- हमारे देश का गरीब भी आर्थिक विकास यात्रा की मुख्य धारा में उसको भी जगह मिलनी चाहिए और हमने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की। आज करीब 32 करोड़ ऐसे लोग जिनके बैंक में खाते खोल दिए गए। और भाइयो, बहनों जब बैंक का खाता खोला तब हमने कहा था कि गरीबों को एक भी रुपया दिए बिना बैंक का खाता खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। लेकिन मेरे देश का गरीब कहने को भले गरीब हो, जिंदगीभर गरीबी से जूझता हो, लेकिन मैंने ऐसे मन के अमीर कभी देखे नहीं हैं, जो मन का अमीर मेरा गरीब होता है।

मैंने ऐसे अमीरों को देखा है जो मन के गरीब हैं और मैंने ऐसे गरीबों को देखा है जो मन के अमीर हैं। हमने कहा कि जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खुलेगा लेकिन गरीब को लगा- नहीं, नहीं, कुछ तो करना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयो-बहनों, आज मुझे खुशी से आपको कहते हुए गर्व होता है कि जिन गरीबों का जीरो बैलेंस अकाउंट बना था, आज उन गरीबों ने 72 हजार करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जन-धन योजना बैंक अकाउंट में जमा किया है। अमीर बैंक से निकालने में लगा है, मेरा गरीब ईमानदारी से बैंक में जमा करने में लगा है। गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है।

भाइयो-बहनों, आपको मालूम है अगर गैस का चूल्हा चाहिए तो कितने नेताओं के पीछे घूमना पड़ता था छह-छह महीने तक। एक पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलते थे कि आप एक साल में 25 परिवारों को गैस का कनेक्शन दे करके oblige कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी एमपी की खबरें आया करती थीं कि वो कूपन को भी ब्लैक में बेच देते थे।

भाइयो-बहनों, क्या आज भी मेरी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में जिंदगी गुजारे? क्या गरीब का कल्याण ऐसे होगा? हमने फैसला लिया कि मेरी गरीब माताएं-बहनें जो लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में खाना पकाती हैं, एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। और घर में जो बच्चे खेलते हैं वो भी धुएं के मारे, मारे जाते हैं।

भाइयो-बहनों, हमने बीड़ा उठाया। गरीब का भला करना है नारों से नहीं होगा। उसकी जिंदगी बदलनी होगी और हमने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 3 करोड़ 30 लाख परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। लकड़ी का चूल्हा, धुएं की मुसीबतें- इन करोड़ों माताओं को मुक्त कर दिया। आप मुझे बताइए हर दिन जब चूल्हा जलाती होगी, गैस पर खाना पकाती होगी, वो मां नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी की नहीं देगी? वो मां हमारी रक्षा करने के लिए प्रण लेती होगी कि नहीं लेती होगी? क्योंकि उसे पता है कि गरीबी से लड़ाई लड़ने का ये सही रास्ता नजर आ रहा है।

भाइयो-बहनों, आजादी के 70 साल के बाद 18 हजार गांव, जहां बिजली न पहुंची हो। आप मुझे बताइए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन वो तो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है। उसके मन में सवाल उठता है- क्या ये आजादी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये मैं बटन दबा करके सरकार बनाता हूं? क्या ये सरकार है जो मुझे आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंचाती है? और भाइयो-बहनों, ये 18 हजार गांवों को बिजली पहुंचाने का मैंने बीड़ा उठाया। अब करीब 2000 गांव बचे हैं, काम चल रहा है तेजी से। 21वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए उनको अवसर मिला।

आजादी के 70 साल बाद आज भी चार करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी तब तक इन चार करोड़ परिवारों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बच्चे पढ़ेंगे। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो गरीबों को empower करना पड़ता है। ऐसी अनेक चीजें हम ले करके चल दिए हैं।

भाइयो-बहनों, ये रिफाइनरी भी यहां की तकदीर भी बदलेगी, यहां की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी-रोटी का प्रबंध होगा। और वो कारखाने की चारदिवारी में रोजगार मिलता है, ऐसा नहीं है। उसके बाहर एक chain चलता है। अनेक उसके समर्थन में छोटे-छोटे उद्योग लगते हैं। इतने बड़े उद्योग के लिए infrastructure लगता है। पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचती है, गैस पहुंचती है, Optical Fiber, network पहुंचता है। एक प्रकार से पूरे क्षेत्र के आर्थिक, उसके मानदंड बदल जाते हैं।

और जब इस प्रकार के लोग आएंगे, बड़े-बड़े बाबू यहां रहते होंगे तो अच्छे शिक्षा संस्थान भी अपने-आप वहां बनने लगेंगे। जब इतनी बड़ी मात्रा में देशभर से लोग यहां काम करने के लिए आएंगे, राजस्थान के नौजवान काम करने के लिए आएंगे; कोई उदयपुर से आएगा, कोई बांसवाड़ा से आएगा, कोई भरतपुर से आएगा, कोई कोटा से आएगा, कोई अलवर से आएगा, कोई अजमेर से आएगा; तो उनके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी अच्छी अरोग्य की व्यवस्थाएं बनेंगी जो पूरे इलाके का लाभ करेंगी।

और इसलिए भाइयो-बहनों, पांच साल के भीतर-भीतर यहां कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका आप भलीभांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयो-बहनों, आज मैं एक ऐसे कार्यक्रम को यहां आरंभ करने आया हूं, जिसमें मेरा घाटे का सौदा है। भारत सरकार के लिए घाटे का सौदा है। पुरानी सरकार वाला काम आगे बढ़ा होता तो भारत सरकार के खजाने में करीब-करीब 40 हजार करोड़ रुपये बच जाते।

लेकिन ये वसुंधरा जी- राजपरिवार के संस्कार तो हैं, लेकिन राजस्थान का पानी पीने के कारण वो मारवाड़ी वाले भी संस्कार हैं। उन्होंने ऐसे भारत सरकार को जितना चूस सकती हैं, चूसने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के हित के लिए अपनी ही सरकार दिल्ली में हो तो भी अड़ जाए और अपनी इच्छा मनवा करके रहे।

मैं बधाई देता हूं, वसुंधरा जी को कि उन्होंने राजस्थान के पैसे बचाए और भारत सरकार को योजना सही कैसे बने, उसको करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और उसी का नतीजा है कि आज वसुंधरा जी और धर्मेन्द्र जी ने मिल करके कागज पर लटके हुए इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं इन दोनों को बधाई देता हूं। मैं राजस्थान को बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

मेरे साथ पूरी ताकत से बोलें- भारत माता की- जय

बाइमेर की धरती से अब देश को ऊर्जा मिलने वाली है। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो ऊर्जा यहीं से चल पड़े, देश के हर कोने में पहुंचे, यही शुभकामनाओं के साथ खम्मा घणी।

अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1516872) आगंतुक पटल : 1965

प्रधानमंत्री कार्यालय

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री के भाषण का मूलपाठ

प्रविष्टि तिथि: 11 APR 2018 5:28PM by PIB Delhi

ऊर्जा मंत्री, सउदी अरब

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत

महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम

सम्मानित प्रतिनिधिगण

देवियों और सज्जनों

भारत में आपका स्वागत है

16वीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम मंत्री स्तरीय बैठक में आपका स्वागत है

मैं तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों के ऊर्जा मंत्रियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बड़ी संख्या में भागीदारी से प्रसन्न हूँ।

जैसा कि आप वैश्विक ऊर्जा के भविष्य पर विचार-विमर्श के लिए आज एकत्रित हुए हैं, विश्व ऊर्जा की आपूर्ति और खपत में बड़ा परिवर्तन देख रहा है।

- खपत वृद्धि का रुख गैर ओईसीडी देशों: मध्य पूर्व, अफ्रीका और विकसित एशिया की ओर हो गया है;
- अन्य सभी ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर फोटो वाल्टिक ऊर्जा किफायती हो गई है। यह आपूर्ति परिप्रेक्ष्य में बदलाव कर रहा है;
- एलएनजी और प्राकृतिक गैस के बढ़ते प्रतिशत के साथ विश्व में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में योगदान कर रही है;
- अमेरिका शीघ्र तेल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। अगले कुछ दशकों में तेल की अतिरिक्त मांग का बड़ा हिस्सा अमेरिका पूरा करेगा;
- ओईसीडी विश्व में और बाद में विकासशील देशों में प्राथमिक ऊर्जा में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कोयला धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा;
- अगले कुछ दशकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाए जाने के बाद परिवहन क्षेत्र में विशाल परिवर्तन होगा;
- विश्व सीओपी-21 समझौते के आधार पर जलवायु परिवर्तन एजेंडा के प्रति संकल्पबद्ध है। अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा तीव्रता हरित ऊर्जा और ऊर्जा सक्षमता पर फोकस के साथ बदलेगी।

पिछले महीने एक एजेंसी द्वारा तैयार की ऊर्जा भविष्यवाणी मुझे देखने को मिली, जिसके अनुसार भारत अगले 25 वर्षों में वैश्विक ऊर्जा मांग का प्रमुख प्रेरक होगा। अगले 25 वर्षों में भारत की ऊर्जा खपत प्रति वर्ष 4.2 प्रतिशत बढ़ेगी। यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि 2040 तक गैस की मांग तिगुनी हो जाएगी। 2030 तक बिजली से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़कर 320 मिलियन हो जाएगी। आज यह संख्या 3 मिलियन है।

हम ऊर्जा पर्याप्तता के युग में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी 1.2 बिलियन लोगों को अभी भी बिजली नहीं मिल रही है। काफी अधिक लोगों के पास स्वच्छ रसोई ईंधन नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्थिति वंचित लोगों के लिए अहितकर न हो और लोगों को सार्वभौमिक रूप से स्वच्छ, किफायती सतत और समान ऊर्जा सप्लाई हो।

मुझे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के हमारे प्रयासों पर अपना विचार साझा करने का अवसर दें।

तेल और गैस कारोबार की सामग्री है, लेकिन आवश्यकता की भी। चाहे साधारण आदमी के लिए रसोई हो या विमान हो ऊर्जा आवश्यक है।

विश्व ने एक लंबे समय से मूल्यों में उतार-चढ़ाव देखा है।

हमें आवश्यक रूप से उत्तरदायित्व मूल्य व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों के बीच संतुलन कायम करें। तेल और गैस दोनों के लिए हमें पारदर्शी और लचीले बाजार की आवश्यकता है। तभी हम अधिक से अधिक रूप में मानवता की आवश्यकता के लिए ऊर्जा दे सकते हैं।

यदि विश्व को सम्पूर्ण रूप से विकसित होना है तो उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच पारस्परिक रूप से समर्थनकारी संबंध बनाने पड़ेंगे। अन्य व्यवस्थाओं का तेजी से बढ़ना उत्पादकों के हित में है। इसे उनके लिए विकसित हो रहे ऊर्जा बाजार सुनिश्चित होंगे।

इतिहास हमें दिखाता है कि कृत्रिम रूप से मूल्यों को तोड़ने-मड़ने का प्रयास आत्मघाती है। ऐसे प्रयास अनुचित कठिनाइयां पैदा करते हैं, विशेषकर विकसित और कम विकसित देशों के उन लोगों के लिए जो निचली पायदान पर हैं।

आइए, हम इस मंच का उपयोग उत्तरदायित्व मूल्यों व्यवस्था पर वैश्विक सहमति बनाने में करें, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की पारस्परिक हितों को लाभ हो।

वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए भारत को भी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है। भारत की ऊर्जा भविष्य के लिए मेरे विजन के चार स्तंभ हैं- ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सक्षमता, ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा सुरक्षा।

भारत के भविष्य के लिए साधारण रूप से ऊर्जा और विशेष रूप से हाइड्रो कार्बन मेरे विजन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भारत को वैसी ऊर्जा की आवश्यकता है जो प्राप्त होने योग्य और गरीबों के लिए किफायती हो। ऊर्जा के उपयोग में सक्षमता आवश्यक है। देशों के समूह में उत्तरदायी वैश्विक सदस्य के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, उत्सर्जन नियंत्रण और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

मित्रो,

वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। सभी प्रमुख एजेंसियां जैसे – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने निकट भविष्य में भारत की विकास दर 7 से 8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। सरकार मुद्रा स्फीति की दर कम करने, वित्तीय घाटे पर नियंत्रण और विनिमय दर को स्थिर करने के साथ उच्च विकास दर हासिल करने में सक्षम हुई है। वृहद अर्थनीति में इस स्थिरता ने अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश को बढ़ावा दिया है।

भारत के पास जनसंख्या के ढांचे में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की संभावना है, खासतौर से जब कार्यशील आबादी का आयु वर्ग, गैर-कार्यशील आबादी से बड़ा है। हमारी सरकार मेक इन इंडिया और वस्त्र, पेट्रो रसायन, रक्षा, इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों में युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के जरिये स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है। परिणामस्वरूप ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिला है।

हम कच्चा माल निकालने अथवा उत्पादन की अपनी नीतियों और नियमों में नयापन लाए हैं। इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति की शुरूआत के जरिये क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता स्थापित की है। बोली लगाने के मानदंड की जगह राजस्व साझा किया जा रहा है। इससे सरकार के हस्तक्षेप को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में बोली का दौर 2 मई तक खुला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हमारे प्रयास में शामिल हो। ओपन एकरेज और राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रह उन क्षेत्रों में कंपनियों की भागीदारी में मदद करेगा, जिनमें उनकी दिलचस्पी है और भारतीय क्षेत्रों में अन्वेषण हित बढ़ाने में मदद मिलेगी।

परिष्कृत तेल पुनः प्राप्ति नीति का उद्देश्य उच्च स्तर वाले क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

बाजार की प्रवृत्ति से निर्देशित पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कच्चे तेल के परिष्करण प्रसंस्करण के साथ-साथ उससे प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग और उनका वितरण पूरी तरह उदार हो गया है। हम ईंधन के रिटेल और भुगतान में डिजिटल मंच की ओर बढ़ चुके हैं।

हमारी सरकार ने समूचे तेल और गैस मूल्य श्रृंखला में अप स्टीम उत्पादन से लेकर डाऊन स्टीम रिटेल में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है।

हमारी सरकार ऊर्जा नियोजन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण में विश्वास करती है और भारत में हमारा ऊर्जा एजेंडा समग्र, बाजार आधारित और जलवायु के प्रति संवेदनशील है। हमारा मानना है कि इससे संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास एजेंडा के ऊर्जा से जुड़े तीन घटकों को हासिल करने में सफलता मिलेगी, जो इस प्रकार हैं –

2030 तक आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच;

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई – पेरिस समझौते की तर्ज पर;

वायु की गुणवत्ता में सुधार के उपाय;

मित्रों, हमारा मानना है कि खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन लोगों के रहन-सहन का स्तर सुधारने में बेहद महत्व रखता है। इससे महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिलता है। इससे घर के अंदर प्रदूषण कम होता है और जैव ईंधन और लकड़ी एकत्र करने में आने वाली कठिनाइयां कम होती हैं। इससे उन्हें अपने विकास के लिए अधिक समय मिलता है और वे अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकती हैं।

भारत में, उज्ज्वला योजना के जरिये हम गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आठ करोड़ गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना है। दो वर्ष से भी कम समय में 3.5 करोड़ कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

हमारा अप्रैल 2020 तक बीएस-6 ईंधन तक पहुंचने का प्रस्ताव है, जो यूरो-6 मानकों के बराबर है। हमारे तेल शोधक संयंत्रों का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जा रहा है। उनका लक्ष्य स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी समय सीमा को पूरा करना है। नई दिल्ली में हमने इस महीने बीएस-6 मानक के ईंधन की शुरूआत कर दी है।

हमने वाहनों को हटाने की नीति भी शुरू की है, जिससे पुराने वाहनों के स्थान पर स्वच्छ और कम ईंधन खर्च करने वाले वाहनों को लाया जा सकेगा।

हमारी तेल कंपनियां ऊर्जा, विविधता को ध्यान में रखते हुए अपने सभी निवेशों का आकलन कर रही हैं।

आज, तेल कंपनियां वायु और सौर क्षमताओं, गैस संबंधी बुनियादी ढांचे में भी निवेश कर रही हैं और इलेक्ट्रिक वाहन और भंडारण क्षेत्रों में निवेश करने की दिशा में भी विचार कर रही हैं।

मित्रो,

जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ देख रहे हैं, जिसमें नई प्रौद्योगिकी के साथ भविष्य में उद्योग के कार्य करने के तरीके और इंटरनेट जैसी प्रक्रियाओं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, मशीन सीखने, भविष्य सूचक विश्लेषण संबंधी, 3-डी प्रिंटिंग आदि में परिवर्तन के विचार को शामिल किया गया है।

हमारी कंपनियां नवीनतम प्रौद्योगिकी अपना रही हैं। इससे हमारी प्रभावोत्पादकता में सुधार आएगा और सुरक्षा बढ़ने के साथ न केवल डाउनस्ट्रीम रिटेल में बल्कि अपस्ट्रीम तेल उत्पादन, परिसम्पत्ति के रखरखाव और रिमोट निगरानी में होने वाला खर्च कम होगा।

इस पृष्ठ भूमि में ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य पर विचार करने के लिए भारत ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। वैश्विक परिवर्तन, पारगमन नीतियां और नई प्रौद्योगिकी किस प्रकार बाजार की स्थिरता और भविष्य में क्षेत्र में निवेश को प्रभावित करती है।

मित्रो,

आईईएफ-16 का विषय 'द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी' है। मुझे बताया गया है कि इसका एजेंडा उत्पादक-उपभोक्ता संबंधों में वैश्विक परिवर्तन, ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच और वहनीयता तथा तेल और गैस में निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषय रखे गये हैं, ताकि भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके। ऊर्जा सुरक्षा और नई और वर्तमान प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और सह-अस्तित्व पर भी विचार किया गया है। ये सभी हमारी सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य के विषय हैं।

मुझे विश्वास है कि इस मंच पर होने वाले विचार-विमर्श से दुनिया के नागरिकों को स्वच्छ, सस्ती और निरंतर ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा।

मैं इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

एकेटी/वीके/एएम/एजी/केपी/जीआरएस/एसकेपी -

(रिलीज़ आईडी: 1528672) आगंतुक पटल : 307

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English

प्रधानमंत्री कार्यालय

श्रीनगर में किशनगंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 19 MAY 2018 6:30PM by PIB Delhi

मंच पर उपस्थित जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान एन.एन.वोहरा जी, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, डॉक्टर जितेन्द्र सिंह जी, आर.के. सिंह जी, जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री श्रीमान कवींद्र गुप्ता जी, राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, विधान सभा के डिप्टी स्पीकर श्री नजीर अहमद खान जी, सांसद और देश के वरिष्ठ नेता, आदरणीय डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला जी, सांसद श्रीमान मुज्जफर हुसैन बैग जी, और यहां उपस्थित सभी अन्य महानुभाव और जम्मू-कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयो और बहनों।

एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में आप सभी के बीच आने का अवसर मुझे मिला है। आपका अपनापन, अपना स्नेह ही जो मुझे बार-बार खींचकर यहां लाता है। बीते चार वर्ष में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मेरा यहां आना नहीं हुआ है। जब श्रीनगर में बाढ़ के बाद भी दिवाली थी, मैं यहां पीड़ितों के बीच ही अपनी दिवाली मनाई थी। इसके अलावा सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने का मुझे अवसर मिला और आज जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है तब भी मैं आपके बीच में हूँ। ये महीना पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे की सीख ही सही मायने में देश और दुनिया को आगे ले जा सकती है।

ये भी सुखद संयोग है कि रमजान के इस मुबारक महीने में हम यहां एक बहुत बड़े सपने को पूरा होने पर इक्ठा हुए थे। आज मुझे Kishanganga Hydro Electric Project को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कई मुश्किलों से पार पाने के बाद ये प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। अस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इससे राज्य को सिर्फ मुफ्त ही नहीं, बल्कि पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। अभी जम्मू-कश्मीर को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसका एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे हिस्से से पूरा किया जाता है। 330 मेगावाट की इस परियोजना के शुरू होने से बिजली की कमी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।

भाइयो और बहनों, ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। इसे पूरा करने के लिए अनेक लोगों ने तपस्या की है। पहाड़ के सीने को चीर करके किशनगंगा के पानी को tunnel के जरिए बांदीपोरा के बोनार नाले में पहुंचाया गया। इस परियोजना से जुड़े हर कामगार, हर कर्मचारी, हर इंजीनियर सब को ही विशेष बधाई के पात्र हैं। आपके ही हौसले का परिणाम है कि इस मुश्किल प्रोजेक्ट को हम पूरा कर पाए हैं।

अभी यहां इस मंच से मुझे श्रीनगर रोड के, रिंग रोड के शिलान्यास का भी अवसर मिला है। Forty two किलोमीटर की इस सड़क पर five hundred करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये रिंग रोड श्रीनगर शहर के भीतरी इलाकों में जो जाम की समस्या है उसको काफी हद तक कम करने का कार्य करेगी, आपकी जिंदगी आसान बनाएगी।

साथ में जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए राज्य के तीनों हिस्सों कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का संतुलित विकास बहुत ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ढाई साल पहले 80 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया था। मुझे खुशी है इतने कम समय में लगभग sixty three thousand करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है और 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इस राशि से जम्मू-कश्मीर में IIT बनाने का काम, IIM बनाने का काम, दो AIIMS बनाने का काम, प्राथमिक चिकित्सालयों से लेकर जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है।

नए नेशनल हाइवे, ऑलवेदर रोड, नई सुरंगें, पावर ट्रांसमिशन और distribution line, नदियों और झीलों का संरक्षण, किसानों के लिए योजनाएं, cold storage, वेयरहाउसिंग, नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर ये अनेक नए initiative लिए जा रहे हैं। 21वीं सदी का जम्मू-कश्मीर यहां के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इस पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।

साथियों, जब भी मैं पहाड़ पर जाता हूं एक कहावत जरूर याद आती है। पहले कहा जाता था की पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। ये कहावत तब की है जब आधुनिक तकनीक का उतना प्रसार नहीं हुआ था, इंसान प्रकृति के सामने मजबूर था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस कहावत को आप सभी के सहयोग से हम बदलने में जुटे हैं। जम्मू-कश्मीर का पानी और यहां की जवानी, दोनों इस धरती के काम आने वाले हैं।

जम्मू-कश्मीर में कई नदियां हैं जहां जल-विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। ये देश का वो हिस्सा है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि देश के लिए भी बिजली पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते चार वर्षों से हम यहां अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनने वाले hydro power plant पर भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के हर घर तक बेरोकटोक बिजली पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। Smart Grid और Smart meter जैसी Advanced Technology का इस्तेमाल किया जा रहा है। Street Lights का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के गांव से लेकर कस्बों तक को रोशन करने के लिए, राज्य के बिजली Distribution System को सुधारने के लिए लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।

साथियों, सिर्फ गांव और घरों तक बिजली पहुंचाना भर ही मकसद नहीं है। बल्कि जिन घरों में बिजली पहुंच चुकी है उनमें बिजली का बिल बोझ ना बने इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। उजाला योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में भी 78 लाख से अधिक LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे यहां की जनता को जो बिजली में बिल में हर वर्ष करीब-करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। सरकार राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाने की मुहिम में जुटी हुई है। सौभाग्य योजना के तहत अब जम्मू-कश्मीर के हर उस घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम चल रहा है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है।

साथियों जम्मू-कश्मीर में विकास का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई सेक्टर है, तो वो है टूरिज्म, ये दशकों से हम देखते आ रहे हैं। कम निवेश पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला ये सेक्टर जम्मू-कश्मीर के भाग्य का भाग्य विधाता रहा है। लेकिन अब ये सेक्टर पुराने तौर-तरीकों पर नहीं चलता। आज का टूरिस्ट, आज की सुविधाएं चाहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों तक इंतजार नहीं करना चाहता, वो संकरे रास्तों में फंसना नहीं चाहता, वो लगातार बिजली चाहता है, वो साफ-सफाई चाहता है, वो अच्छी हवाई सेवा चाहता है।

टूरिज्म के लिए जिस आधुनिक इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है, उसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेक योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। जितना ये इकोसिस्टम मजबूत होगा, उतना ही जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे, उतना ही आपकी कमाई बढ़ेगी।

साथियों, पूरे विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जहां की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर केंद्रित है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। अकेले जम्मू-कश्मीर में वो क्षमता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की गति और बढ़ा सकने का सामर्थ्य रखता है। अगर मैं सिर्फ टूरिज्म की बात करूं तो लगभग 2 हजार करोड़ रुपए के निवेश से 12 डेवलपमेंट अथॉरिटीज, 3 टूरिज्म सर्किट, 50 टूरिस्ट विलेज बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, टूरिज्म, के साथ ही उसके पूरे इकोसिस्टम को मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक है।

इस इकोसिस्टम का बहुत बड़ा आधार है कनेक्टिविटी। यही कारण है कि कनेक्टिविटी के लिए जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को दिए गए पैकेज का लगभग आधा हिस्सा रोड सेक्टर पर ही खर्च किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है।

यहां आने से पहले, मैंने देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग के कार्य का शुभारंभ किया है। ये टनल जम्मू-कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखने वाली है। आप सोचिए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अक्सर, पढ़ाई के लिए जाते हुए, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए, इलाज के लिए जाते हुए, व्यापार के लिए आते-जाते समय, सामान की खरीद-बिक्री के समय, आपको परेशान कम होना पड़ेगा। रास्ते में देरी के चलते जो हमारे सेब खराब हो जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाती हैं, यहां के किसानों का जो नुकसान होता है, वो भी हम बहुत बड़ी मात्रा में कम कर सकेंगे।

यहां श्रीनगर में बनने वाली रिंग रोड हो, श्रीनगर-शोपियां-काज़ीगुंड नेशनल हाईवे हो या फिर चेनानी-सुधमहादेव-गोहा रोड हो, इनके पूरा होने पर आप लोगों का समय भी बचेगा और संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। राज्य के ऐसे इलाके जो बर्फबारी में महीनों के लिए कट जाते हैं, उन्हें भी जोड़ा जा रहा है, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराई जा रही है। ये भी आपकी जानकारी में है कि सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी काम प्रगति पर है।

शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अमृत योजना के तहत लगभग साढ़े 5 सौ करोड़ व्यय किए जा रहे हैं। जब आधुनिक सुविधाएं होंगी, आधुनिक सड़कें होंगी, तो आपकी जिंदगी तो आसान बनेगी ही, जम्मू-कश्मीर में, उसकी सुंदरता में भी और नए चार चांद लगाने वाले हैं।

भाइयों और बहनों, जब हम गांव और शहरों को Smart बनाने की बात करते हैं तो स्वच्छता इसका एक अहम हिस्सा है। मुझे खुशी है कि जम्मू-कश्मीर की जनता भी इस अभियान को पूरी शक्ति से आगे बढ़ा रही है।

हाल में यहां की एक बिटिया का वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा था। पांच साल की 'जन्नत' डल लेक को साफ करने के लिए मिशन में जुटी है। जब देश का भविष्य इतना पवित्र और स्वच्छ सोचता है, तब मुझे इस अभियान का एक सदस्य होने के नाते और भी खुशी होती है। साथियों, ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने स्तर पर इस प्रकार के काम कर रहे हैं।

भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का एहसास है कि भीषण बाढ़ ने यहां जो तबाही फैलाई उसने आपके जीवन को बदलकर रख दिया है। हमारा ये हर संभव प्रयास है कि जहां-जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। और इसके लिए राज्य सरकार की निरंतर मदद की जा रही है।

साथियों, एक और बहुत गंभीर विषय है जिस पर पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। ये विषय है विस्थापितों का। जो लोग सीमा पार के हालात से तंग होकर यहां आए हैं, जिन्हें स्थानीय समस्याओं की वजह से घर छोड़ना पड़ा है, अलग-अलग जगहों पर उनके पुनर्वास के लिए करीब-करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

साथियों, आज जम्मू-कश्मीर के अनेक युवा, देश के दूसरे राज्यों के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। सिविल सेवा में जब यहां के नौजवानों का नाम देखता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, तो मेरी खुशी दोगुना हो जाती है। मुझे याद है देश का सीना तब गर्व से चौड़ा हो गया था, जब यहां बांदीपोरा की बिटिया ने किक बॉक्सिंग में भारत

का नाम रोशन किया। तजामुल जैसे Talent को देश बेकार नहीं जाने दे सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के Sporting Talent को निखारने के लिए राज्य सरकार के साथ मिल करके प्रयास कर रही है। इसी भावना के तहत यहां Sports Infrastructure विकसित करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है।

भाइयों और बहनों, जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर कई नई योजनाओं को साकार किया गया है। हिमायत स्कीम के तहत यहां के एक लाख नौजवानों को ट्रेड करने की योजना पर काम चल रहा है। 16 हजार से ज्यादा बच्चों को प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ मिला है। उन्हें देश के बेहतरीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का अवसर दिया गया है। अलग-अलग वजहों से कॉलेज और स्कूल बीच में छोड़ने वाले लगभग 60 हजार विद्यार्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया है।

यहां के नौजवान देश और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा में काम आ सके, इसके लिए भी नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस को सशक्त करने के लिए 5 Indian Reserve Battalion स्वीकृत की गई है। मुझे बताया गया है कि भर्ती की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जिसके बाद यहां के 5 हजार युवाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलगा।

भाइयों और बहनों, हमारी सरकार के लिए नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं, यहां जम्मू-कश्मीर की पुलिस हो, Paramilitary Forces और सेना के जवान हों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल हालात में भी आप शानदार काम कर रहे हैं। आपके बीच जो मेल-जोल है, कॉर्डिनेशन है, उसके लिए ये सभी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे बाढ़ हो या फिर, बर्फ़ीले तूफान हों या फिर आग जैसी आपदाएं हों, मुश्किल में फंसे हर जम्मू-कश्मीर वासी के लिए सुरक्षाबलों का योगदान अतुलनीय है। यहां की जनता के लिए वे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कष्ट झेल रहे हैं उसकी एक-एक तस्वीर देश की जनता के दिलों-दिमाग में छाई हुई है।

भाइयों और बहनों देश के सवा सौ करोड़ लोग आज New India के संकल्प पर काम कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर इस New India का सबसे चमकता सितारा बन सकता है। कोई वजह नहीं कि जम्मू-कश्मीर में देश के सबसे अच्छे शिक्षा संस्थान, सबसे अच्छे अस्पताल, सबसे अच्छी सड़कें, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, न हों। कोई वजह नहीं कि यहां के हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर न बनें, अच्छे इंजीनियर न बनें, अच्छे प्रोफेसर और अच्छे अधिकारी न बनें, कोई कारण नहीं है।

साथियों, बहुत सारी शक्तियां हैं, जो नहीं चाहती कि जम्मू-कश्मीर का विकास हो, यहां के लोगों का जीवन खुशहाल हो, लेकिन साथियों हमें इन विदेशी ताकतों को जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है।

यहां महबूबा मुफ्ती जी के नेतृत्व में चल रही पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार निरंतर ऐसे नौजवानों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है, जो विदेशी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अपनी ही पवित्र धरती पर प्रहार कर रहे हैं।

साथियों, शांति और स्थायित्व का कोई विकल्प नहीं होता है। मेरा आग्रह है कि जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं, वो मुख्य धारा में वापिस लौटें। ये मुख्य धारा है, उनका परिवार, उनके माता-पिता। ये मुख्य धारा है जम्मू-कश्मीर के विकास में उनका सक्रिय योगदान। इस युवा पीढ़ी पर ही जिम्मेदारी है जम्मू-कश्मीर का गौरव, बढ़ाने की। जम्मू-कश्मीर में इतने साधन हैं, इतने संसाधन हैं, इतना सामर्थ्य है, कि कोई वजह नहीं कि जम्मू-कश्मीर, भारत के अपने दूसरे क्षेत्रों से रत्ती भर भी पीछे रहे। भटके हुए नौजवानों द्वारा उठाया गया हर पत्थर, हर हथियार, उनके अपने जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करता है।

राज्य को अब अस्थिरता के इस माहौल से बाहर निकलना ही होगा। भविष्यके लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन्हें सिर्फ कश्मीर ही नहीं, भारत के विकास की मुख्यधारा से भी जुड़ना होगा। हजारों वर्षों से, हम एक भारत मां की संतानें हैं। दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो भाई को भाई से दूर कर सकती है। मां के दूध में कभी

दरार नहीं हो सकती। जो लोग दशकों से इस प्रयास में लगे हुए थे, वो अब खुद बिखरने की कगार पर हैं।

भाइयों और बहनों मैं फिर कहूंगा, पिछले वर्ष मैंने दीवाली गुरेज़ में जवानों के साथ मनाई थी तो इस वर्ष रमज़ान के मौके पर यहां आप सबके बीच में हूं। यही तो कश्मीर की भावना है, यही तो इस धरती की देश और दुनिया को देन है। यहां सबका स्वागत है, यहां सबका सत्कार है। ये उस परंपरा की धरती है जो देश-दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसी धरती को पंथ और संप्रदायों से ज्यादा परंपराओं ने सींचा है। इसलिए-

कश्मीरियत के अटल जी भी कायल रहे हैं और इसी कश्मीरियत का मोदी भी मुरीद है।

और मैंने तो लालकिले से भी कहा था कि:

न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझेगी, हर कश्मीरी को गले लगाने से समस्या सुलझेगी।

जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के पास नीति भी है, नीयत भी है, और निर्णय लेने में भी हम कभी पीछे नहीं रहते हैं। छात्रों पर हजारों मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया हो या फिर अभी रमज़ान के इस मुबारक महीने में लिया गया सीज फायर का फैसला, उसके पीछे की सोच यही है कि कश्मीर के हर नौजवान को, यहां के हर व्यक्ति को स्थायित्व मिले, स्थिरता मिले और विकास मिले।

साथियों, ये सिर्फ सीजफायर नहीं है, ये इस्लाम की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को उजागर करने का एक माध्यम भी है। मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की जाती रही है। स्थायित्व की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया है। वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से, यहां के अलग-अलग संगठन-संस्थाओं से मिल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो भी अपनी बात है जाके बताएं। हर व्यक्ति से बातचीत करके वो शांति प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

भाइयों और बहनों, सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन कश्मीरियत और जम्मूरियत के गठबंधन को कायम रखने में आप सभी लोगों की भी और मैं जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं आप सभी की भी, यहां के हर माता-पिता की, यहां के युवाओं की, बुद्धिजीवियों की और धर्मगुरुओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी भूमिका है।

मैं चाहूंगा कि आप, हम, सभी अपनी सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ जम्मू-कश्मीर के विकास पर लगाएं। हर समस्या, हर विवाद, हर मतभेद का, उसका हल एक ही है- विकास, विकास, और सिर्फ विकास।

New India के साथ ही New Jammu-Kashmir, शांत और समृद्ध जम्मू-कश्मीर बदलते भारत की विकास गाथा को और मजबूत करेगा, और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में भी अपनी भावनाओं को मैं खोल करके प्रकट करता हूं। अपनी बात को खोल करके बताता हूं। और मैं दुनिया के लोगों को भी कहता हूं- सारी दुनिया के देश, जो भी इन रास्तों पर चल पड़े हैं, सारे पछता रहे हैं। सब वापस लौट रहे हैं। वो वापिस लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इसलिए अमन-चैन की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी, शांति और समृद्धि की जिंदगी, सुख-चैन की जिंदगी, इसी विरासत को हमने आगे बढ़ाना है और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। जहां जरूरत होगी सारे कदम उठाते चले जाएंगे। आपका साथ और सहयोग रहेगा; हम जिस चाह को ले करके निकले हैं वो चाह हम पूरी करके रहेंगे और फिर एक बार हमारा ये कश्मीर, हमारा ये जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख, पूरा इलाका सारे हिन्दुस्तानियों के लिए वही मुकुट मणि के रूप में हर किसी को प्यार से गले लगाने का मौका देगा।

इसी भावना के साथ सेठा-सेठा शुक्रिया, अज़ दीयू इज़ाजत, खुदाई थई नव खोशत खुशहाल

धन्यवाद

अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1533842) आगंतुक पटल : 61

प्रधानमंत्री कार्यालय

जम्मू में पाकल दुल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखने तथा अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 19 MAY 2018 11:35PM by PIB Delhi

मेरे प्यारे भाई बहनों।

काफी पुराने-पुराने चेहरे हमारे चमनलाल जी जैसे मैं देख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के लिए आज का ये दिन बेहद अहम है। राज्य में ये मेरा आज चौथा कार्यक्रम है। आज सुबह से ही लेह-लद्दाख के ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से, कश्मीर की घाटियों से होते हुए अब जम्मू की तराई तक, विकास की बहती धारा को मैं देख रहा हूँ। और इसी कार्यक्रमों के सिलसिले में मैं लेट भी हो गया। समय पर नहीं पहुँच पाया इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ।

लेह को शेष भारत से कनेक्ट करने वाली Zojila Tunnel हो, बांदीपोरा का किशनगंगा प्रोजेक्ट हो या फिर किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बनने वाला Hydro Power Project, जम्मू-कश्मीर की 'खुशहाली का एक नया द्वार' खुल रहा है। जम्मू-कश्मीर की जल धारा आने वाले समय में यहां कि विकास धारा को गति देने वाली है।

एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करना तो दूसरे का शिलान्यास करना; आज का ये दिन अद्भुत और यादगार दिन बन गया। थोड़ी देर पहले मुझे जम्मू के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इसमें से दो माता वैष्णो देवी को समर्पित हैं। यहां अभी पकल दुल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया। ये कितना लाभकारी होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि, जितनी बिजली आज जम्मू-कश्मीर में पैदा होती है उसकी एक तिहाई इसी एक पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली है।

ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। एक हजार मेगावाट का यह प्रोजेक्ट रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। 8 हजार करोड़ की ये परियोजना यहां रोज़गार के अनेक अवसर पैदा करने वाली है। लगभग ढाई हजार लोगों को तो सीधा-सीधा रोज़गार मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहां के कोई सब्जी उगाने वाले होंगे, कोई दूध बेचने वाले होंगे। अरे हर प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक नया अवसर, नया लाभ का अवसर होने वाला है।

साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को लेकर एक नई अग्रोच के साथ काम कर रही है। ये अग्रोच है Isolation to Integration. यानि देश के जो भी इलाके, किसी भी वजह से अलग-थलग पड़ गए, विकास की रोशनी जहां नहीं पहुँच पाई, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और यही कारण है कि चाहे North-East हो या फिर जम्मू कश्मीर, हमारा प्रयास रहा है कि जितना अधिक हो सके मैं अगर वहां पहुँच सकता हूँ मैं खुद भी पहुँचने का प्रयास करूँ। मुझे खुशी है। पहले किसी प्रधानमंत्री को ऐसा अवसर मिला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। राजनीतिक कामों के सिवाय शायद मैं एक दर्जन से अधिक बार जम्मू-कश्मीर आया हूँ प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पहले तो खैर आप लोगों ने मुझे काफी दिन रखा है, मेरा लालन-पालन किया है आप लोगों ने।

कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट के सूत्र पर हम काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहे रास्तों के जरिए हो या फिर दिलों की, किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए भी हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इस राज्य को New India का Rising Star बनाने की ताकत रखते हैं। ज़रा भारत के उस MAP की कल्पना करिए, जब देश का सरताज हीरे के मुकुट की भाँति चमकेगा और यही चमक बाकी देश को विकास की राह दिखाएगी।

भाइयों और बहनों, और इसी मिशन के साथ केंद्र सरकार राज्य की सरकार के साथ मिल करके हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं धरती पर उतार रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जम्मू शहर को जाम मुक्त करने के लिए, यहां की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए रिंग रोड का शिलान्यास किया गया। अगले 3 वर्षों में इस रिंग रोड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जब ये रिंग रोड बन जाएगा तो आप सभी जम्मू वासियों को और यहां आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी।

और आप देख लीजिए जो लोग डेवलपमेंट के डिजाइन को समझते हैं, ये करीब 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लम्बा रिंग रोड, ये अपने-आप में एक नया जम्मू बसा देगा। इसके दोनों तरफ एक नया जम्मू बस जाएगा। यानी किस प्रकार से expansion होगा, विकास कैसा होगा, मैं भलीभाँति इसको देख

पाता हूँ। इससे जम्मू शहर के भीतर और उसके आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम तो कम होना ही होना है, इतना ही नहीं यह रिंग रोड पुंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनूर क्षेत्र के सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों में भी भारी मशीनरी ले जाने वाले सैन्य वाहनों के परिवहन को भी बहुत आसान बनाएगा।

साथियों, आपका ये जम्मू शहर Smart City मिशन के तहत चुना गया है। यहां Traffic से लेकर Sewage तक, Smart व्यवस्थाएं तैयार हो रही हैं। राज्य सरकार इस काम में जुटी है। केंद्र से इस काम के लिए पैसा भी स्वीकृत किया जा चुका है।

भाइयों और बहनों, विकास के लिए हमारा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है- Highway हो, Railways हो, Waterways हो, i-Ways हो, Roadways हो, ये सारे 21वीं सदी की अनिवार्यताएं हैं। सरकार की सोच स्पष्ट है, अगर सवा सौ करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो पहले उसको सरल और सुगम बनाना होगा। दूसरे शब्दों में इसको Smart व्यवस्थाओं का नाम भी आप दे सकते हैं। इसी सोच का परिणाम है कि आज भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में नेशनल हाईवे का जाल बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

जम्मू कश्मीर हो, पश्चिम भारत हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, देश को Highways की लड़ी में पिरोने का ये प्रोजेक्ट है। इस साल के बजट में इस योजना के तहत बनने वाले लगभग 35 हजार किलोमीटर रोड के लिए 5 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जम्मू-कश्मीर में भी इस योजना के तहत लगभग two thousand seven hundred करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में, यहां भी हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जम्मू को श्रीनगर और देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली हजारों करोड़ की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन पर तेज़ी से काम चल रहा है। जम्मू-पुंछ, उधमपुर-रामबन, रामबन-बनिहाल, श्रीनगर-बनिहाल और काज़ीगुंड-बनिहाल जैसे कई हाईवे प्रोजेक्ट्स, आज उस पर काम चल रहा है और जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए Life Line साबित होने वाले हैं। लगभग 15 हजार करोड़ रुपए इन सड़कों पर खर्च किया जाना है। इसके अतिरिक्त गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। बीते दो वर्षों में लगभग एक लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें इस योजना के तहत बनाई जा चुकी हैं। जम्मू-कश्मीर के गांव में भी बीते दो साल में साढ़े तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई गई हैं।

साथियों, जम्मू-कश्मीर के लिए टूरिज्म आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विशेषतौर पर यहां आस्था से जुड़े बड़े स्थान हैं। बाबा बर्फानी हों या फिर माता रानी का दरबार, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां जुटते हैं। आस्था से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलें और यहां की जनता को रोज़गार के अवसर मिले, इसके लिए अनेक प्रयास सरकार कर रही है।

आज कटरा में माता के दरबार तक रेल पहुंच गई है। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही मुझे इस रेल रूट का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इस रेल रूट से माता के भक्तों को बहुत सुविधा मिली है। हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते, यही कारण है कि आज दो बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। एक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है तो दूसरा माता के द्वार तक सामान पहुंचाने के लिए रोपवे।

साथियों, माता के दर्शन के लिए अब श्रद्धालु ताराकोटा मार्ग से भी जा सकेंगे। कटरा और अर्द्धकुंवारी के बीच पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये वैकल्पिक पैदल मार्ग है। इससे भीड़भाड़ से भी छुटकारा मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस मार्ग को डेढ़ किलोमीटर के लिंक रोड के द्वारा मौजूदा पैदल मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। ताकि पैदल यात्री मंदिर तक यात्रा करने के लिए दोनों उपलब्ध मार्गों में से किसी एक को चुन सकें। माता रानी के भक्तों के लिए यह पूरी तरह से सुखद और सुरक्षित मार्ग है। जिसमें उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है।

साथियों, वैकल्पिक मार्ग के अतिरिक्त माता के द्वार तक Material Ropeway का उद्घाटन का भी आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस Material Ropeway के सहारे सामानों की ढुलाई कहीं ज्यादा आसान होगी। Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board इन अनूठी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर यात्रियों के लिए आसानी से खान-पान की सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा। मंदिर के पास कचरे के प्रबंधन में भी इस रोपवे से बड़ी मदद मिलने वाली है। कटरा से मंदिर तक सामान जाएगा और वहां से वापसी में कचरे को लाया जाएगा।

साथियों, मटीरियल रोपवे की तर्ज पर यात्रियों के लिए भी ऐसी सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा भवन-भैरों घाटी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इस Ropeway की क्षमता प्रतिघंटा 800 लोगों को ले जाने की होगी। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को एक बहुत मदद मिलने वाली है। जब ये रोपवे पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, तो एक बार में 3 मिनट के भीतर 40-45 व्यक्तियों को ले जाया जा सकेगा। इस Ropeway सिस्टम में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम भी होगा। श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए श्राइन बोर्ड जिस प्रकार से काम कर रहा है उसके लिए मैं उसके अध्यक्ष जी को और उसकी पूरी टीम को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

भाइयों और बहनों, जम्मू-कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म से रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन रोज़गार के लिए शिक्षा और कौशल विकास का रोल अहम है। केंद्र सरकार ने राज्य में शिक्षा से जुड़े बड़े संस्थानों को मंजूरी दी है। जम्मू में बनने वाला IIM हो या फिर IIT हो, ये संस्थान राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के 16 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को देश की प्रतिष्ठित Universities और Colleges में पढ़ाई के लिए Scholarship दी गई है।

भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते चार वर्षों में ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक ताकत मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देशभर में लगभग साढ़े 9 करोड़ महिला उद्यमियों ने छोटे-छोटे कारोबार के लिए बिना गारंटी का ऋण प्राप्त किया है। इसमें जम्मू-कश्मीर की 50 लाख से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं।

वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सरकार देश की गरीब माताओं और बहनों को धुआं मुक्त रसोई देने का प्रयास कर रही है। क्लीन कुकिंग- विशेष रूप से गांव की माताएं-बहनें, दलित हों, वंचित हों, पिछड़े हों, ऐसे सभी समाजों से आने वाली माताओं-बहनों के लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। देशभर में जहां लगभग 4 करोड़ मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर में भी साढ़े 4 लाख से अधिक माताओं-बहनों की रसोई तक भी उज्ज्वला पहुंच चुकी है।

साथियों, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। ये सिर्फ स्वच्छता से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि ये महिलाओं के सम्मान का भी विषय है। जम्मू-कश्मीर की माताएं-बहनें इस अभियान को लेकर कितनी जागरूक हैं, इसकी एक मिसाल हाल में ही देश और दुनिया ने देखी। मैंने खुद मीडिया में उधमपुर की 87 साल की बुजुर्ग माता के हौसले को देखा। ये माता इस उम्र में खुद एक-एक ईंट को गारे से जोड़कर टॉयलेट बनाने में जुटी थीं। ना किसी की मदद ना कोई औज़ार, बस एक ही धुन है, स्वच्छता के अभियान से जुड़ने की।

साथियों, ऐसे प्रयास जब होते हैं तो हौसला और साहस अनेक गुना बढ़ जाता है। कहीं 5 वर्ष की बच्चियां इस अभियान से जुड़ रही हैं तो कहीं 87 साल की माताएं जुड़ रही हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता और सम्मान की भावना कितनी गहरी है। यही कारण है कि अब तक ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 80 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में भी इस योजना के तहत लगभग साढ़े 8 लाख घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं।

साथियों, महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण तब तक अधूरा रहेगा जब तक Skill Development पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के कौशल विकास के लिए भी अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 5 हज़ार महिलाओं को Handicrafts, Tailoring, Agriculture और संबंधित व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। भाइयों और बहनों, दो साल पहले जब मैं यहां आया था तब मैंने यहां के नौजवानों से, आप सभी से अपील की थी कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उनका फायदा उठाइए। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहां के नौजवानों ने इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में लगभग 20 लाख लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए हैं। इन खातों में आज की तारीख में लगभग eight hundred करोड़ रुपया जमा है, मैं सिर्फ जम्मू-कश्मीर की बात कर रहा हूं। Un-organised Sector में काम करने वाले जो मेरे श्रमिक भाई-बहनें हैं उनके लिए बनाई गई अटल पेंशन योजना में यहां के 40 हज़ार से अधिक लोग जुड़े हैं। कम प्रीमियम वाली दो जीवन बीमा योजनाएं जो सरकार चला रही है, उनसे राज्य के लगभग 9 लाख लोग जुड़े हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग तीन करोड़ की क्लेम राशी भी दी चुकी है।

साथियों, यहां के नौजवान सेना में भर्ती के लिए हमेशा आगे रहे हैं। परंपरा के मुताबिक ही सुरक्षा बलों में इस राज्य के नौजवानों को बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। Army, Central Armed forces, Police Forces, India Reserve Battalions द्वारा चलाई गई ये special recruitment drives में 20 हज़ार से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं।

साथियों, ये डोगरों की धरती है, ये वीरों की भूमि है। यहां शौर्य भी है, संयम भी है, तो यहां मधुर संगीत भी है। यहां बासमती के खेतों से आती खुशबू भी है, तो आधुनिक कल कारखानों की गुंजाइश भी पड़ी है। हमारा संकल्प भी मजबूत है और रास्ता भी सही है। मुझे रती भर भी संदेह नहीं कि मां वैष्णो के आशीर्वाद से, और आप सभी के परिश्रम से ये राज्य विकास की नई उंचाइयों को छू करके रहेगा, सिद्धि प्राप्त करके रहेगा।

धन्यवाद।

अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1533840) आगंतुक पटल : 55

प्रधानमंत्री कार्यालय

विश्व जैव ईंधन दिवस के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 10 AUG 2018 7:51PM by PIB Delhi

यहां उपस्थित समाज के अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों!

साथियों, अगस्त का ये महीना अपने-आप में पवित्रता और संकल्प का वातावरण लेकर आता है। ये क्रांति का देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित करने वाले सैनानियों को याद करने का महीना होता है। स्वतंत्रता दिवस के साथ ही इस महीने में अनेक त्योहार आते हैं जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आने वाले सभी पर्वों के लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।

हमारी परम्परा में, हमारे उत्सव में, हमारे त्योहारों में प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत ही ऊंचा स्थान है। आज का यह आयोजन भी प्रकृति, पर्यावरण और आधुनिक परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बधाई देता हूँ।

साथियों, सवा सौ करोड़ देशवासियों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, नई-नई योजनाएं बना रही है। गांव की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, गांव के किसान की आय बढ़ाना, पेट्रोल, डीजल, गैस का विकल्प तैयार करना, और पर्यावरण को सुरक्षित करना; ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। बायोफ्यूल, इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है।

साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को; पूरे विश्व की मानव जाति को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल, यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन। ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। और अभी जो फिल्म दिखाई गई, उसमें एक पुरानी कहावत को भी याद किया गया- आम के आम और गुठली के दाम। बहुत पुरानी कहावत है, उसका एक प्रकार से ये आधुनिक रूप है।

बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, देश का धन भी बचाएगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। देश के लिए ये हमारे उस व्यापक vision का हिस्सा है, जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और गांव, गरीब किसान की समृद्धि का रास्ता और मजबूत होने वाला है। इसके अलावा ये हमारे Urban development के आधुनिक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। शहरों में clean energy के तमाम प्रयासों के बीच Biofuel Air Pollution को कम करने में बहुत मददगार है।

साथियों, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई-बहन आज आए हुए हैं और किसान का विज्ञान भवन में आना अपने-आप में एक संकेत है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की स्थिति अलग-अलग है, कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिश का इंतजार है। हम लगातार उन खबरों को देख रहे हैं। कहीं संतोषजनक

बारिश का एक आनंद भी होता है तो कहीं बारिश के कारण परेशानियों से चिंता भी होती है।

खास करके मेरे किसान भाइयों, बहनों- अब तो धान समेत खरीफ की तमाम फसलों की बुवाई में समझता हूँ करीब-करीब देश के हर कोने में पूरी हो चुकी है और आपकी जानकारी में है कि सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना तय किया है। और जब कृषि की बात आती है तो स्वामीनाथन जी का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे यहां लिया जाता है। और मुझे खुशी है कि अभी दो-तीन दिन पहले श्रीमान स्वामीनाथन जी ने एक आर्टिकल के द्वारा कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, सरकार कैसे initiative ले रही है, सरकार की नीतियां किस प्रकार से किसानों की जिंदगी में स्थायी रूप से बदलाव ला रही हैं, बड़ा विस्तार से हो रहा है और वो एक authority है। बहुत विस्तार से उन्होंने भारत सरकार की किसानों से संबंधित जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, प्रयास हैं, उसकी भरपूर सराहना की है।

और आपने भी देखा, फिल्म में भी देखा। खरीफ के मौसम में जो और फसलें होती हैं उसके साथ-साथ गन्ने के लिए भी हमने एमएसपी तय किया है कि किसानों को लागत के ऊपर लगभग 80 प्रतिशत लाभ मिल सके। इस सीजन के गन्ने का लाभकारी मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इस बड़ी हुई कीमत से देश के करोड़ों किसानों को सीधा-सीधा फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त गन्ने से Ethanol बनाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उनका भी लाभ किसानों को मिलना सुनिश्चित है।

साथियों, गन्ने से Ethanol बनाने की योजना पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय काम का प्रारंभ हुआ था। लेकिन बीते एक दशक में, अब जैसा उस सरकार का हाल था, हर योजनाओं का भी वैसा ही हाल होता था; इस प्रयास को भी अति-गंभीरता से नहीं लिया गया। जब 2014 में फिर से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार बनी तो बकायदा एक रोडमैप तैयार किया गया। Ethanol blending program शुरू किया गया। आज देश के 25 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों में ये प्रोग्राम सुचारु रूप से चल रहा है। बीते चार वर्षों में Ethanol का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है और आने वाले चार वर्षों में लगभग 450 करोड़ Ethanol का उत्पादन करने की दिशा में आज देश आगे बढ़ रहा है।

साथियों, इथेनॉल ने न सिर्फ किसानों को लाभ पहुंचाया है बल्कि देश का पैसा भी बचाया है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने से पिछले वर्ष देश को लगभग चार हजार करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले चार वर्ष में ये बचत करीब-करीब 12 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचे। इतना ही नहीं, अगले चार वर्ष में गन्ने से इथेनॉल बनाने भर से ही लगभग 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटने का अनुमान है। इस बचत से और गन्ने के लिए मिले विकल्प से गन्ना किसानों को जो बार-बार मुसीबतों को झेलना पड़ता है उसका एक स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा। इथेनॉल से पैसे की बचत तो हो ही रही है, इसके अलावा पेट्रोल से जो हानिकारक गैस निकलती है, उनमें भी कमी आने वाली है।

साथियों, बायोफ्यूल से जुड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, ये यानी कोई एक wishful thinking हो, बड़ी-बड़ी बातें होती हों, ऐसा नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, ठोस रणनीति बनाई जा रही है, responsibility fix की जा रही है, accountability तय की जा रही है, regular monitoring हो रहा है, टारगेट को पाने का समयबद्ध आयोजन हो रहा है। इथेनॉल समेत बायोफ्यूल के तमाम माध्यमों को विकसित करने के लिए सरकार ने National policy बनाई है। सरकार का ये प्रयास है कि 2022 तक 10 प्रतिशत और 2030 तक यानी दोगुना- 20 प्रतिशत इथेनॉल, पेट्रोल के साथ मिक्स करने की क्षमता विकसित की जा सके।

बायोफ्यूल से सिर्फ गन्ना किसानों को तो एक विकल्प मिलेगा ही, इससे देश के हर किसान को फायदा होने वाला है। हमारे गेहूं, चावल, मक्का, आलू, सब्जियां, हम सब जानते हैं- अक्सर कभी मौसम की वजह से या भंडारण के अभाव के कारण खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, बरबाद हो जाती हैं। और स्वाभाविक है किसान इसको संभाल कर क्या करेगा, वो फेंक देता है। लेकिन अब हमने तय किया है कि इसका इस्तेमाल भी इथेनॉल बनाने के लिए किया जाए।

एक और समस्या किसानों के सामने है कि प्राकृतिक कारणों से फसल में कुछ कमी रह जाती है- जैसे दाग लगना, साइज छोटा होना; ऐसे अनेक कारण होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी फसल बिक नहीं सकती है। जो ग्राहक है वो उसको पसंद नहीं करता, नकार देता है। जो दुकानदार है, वो भी नहीं लेता है और इसके कारण मौसम की आधी-अधूरी मार भी किसान को बहुत नुकसान उठाने के लिए मजबूर करती है। इथेनॉल बनाने के लिए ऐसा सारा भी अनाज होता है- छोटा हो, टूटा-फूटा हो, दाना कम हो, रंग-रूप ठीक न हो, ये सारी चीजें इथेनॉल बनाने के लिए काम आती हैं। और इसमें अगर हम योजनाबद्ध नीति से जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे तो आप विश्वास कर सकते हैं ऐसे में किसानों की फसल का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों की जिंदगी में कितनी बड़ी ताकत आएगी।

साथियो, नेशनल पॉलिसी में सिर्फ फसल से नहीं, बल्कि अब घर से निकलने वाले कूड़े, खेत से निकलने वाले कचरे और पशुओं के गोबर को ईंधन में बदलने के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में केले के छिलके, जो न सिर्फ किसान बल्कि हर घर में कचरे के रूप में आसानी से मिल जाते हैं, वो भी ईंधन के रूप में काम आने वाला है।

इसके अलावा घास और बांस से भी इथेनॉल बनाया जा रहा है। बांस विशेष तौर पर उत्तर-पूर्व और दूसरे आदिवासी इलाके में अच्छी मात्रा में पैदा होता है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण कदम होगा, जो बांस की खेती करने वालों को फायदा करेगा।

साथियो, पराली भी किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। और पता नहीं नासमंझी के कारण, समय के अभाव से, कुछ भी कहो- ये पराली अपने-आप में एक बहुत बड़ी मूल्यवान प्राकृतिक सौगात है। लेकिन अज्ञानवश या आदतों के कारण हम ऐसी मूल्यवान जड़ी-बूटी को जला देते हैं। ये जमीन को नई जिंदगी देने वाली मूल्यवान जड़ी-बूटी हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से जला देते हैं। और मैं तो देख रहा हूं- पंजाब हो, हरियाणा हो- यहां के किसान, ये एक नित्य कार्यक्रम होता है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।

लेकिन मेरे किसान भाइयों को मैं बार-बार समझाता हूं कि इस पराली को जलाने के कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति पर तो असर पड़ता ही है, साथ में इससे निकले धुंए के कारण पूरे पर्यावरण का दुष्प्रभाव पैदा होता है। और इसलिए अब पराली से इथेनॉल बनाने की संभावनाओं पर बहुत व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। यानि अब पराली भी आपको एक इन्कम का स्रोत बन सकती है। और इससे प्रदूषण की भी राहत मिलेगी और किसानों की अतिरिक्त आय भी होगी।

साथियो, biomass को बायोफ्यूल में बदलने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रही है, investment कर रही है। देशभर में दस हजार करोड़ रुपये की लागत से 12 आधुनिक रिफाइनरी बनाने की योजना है। एक रिफाइनरी से लगभग 1000-1500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यानि रिफाइनरी के संचालन से लेकर सप्लाई चेन तक, लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा गोबर से ईंधन बनाने की योजना भी प्रगति पर है।

पिछले बजट में आपने देखा होगा, हमने योजना घोषित की- गोबर-धन। इस गोबर-धन योजना के तहत पूरे देश के हर जिले में एक बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। अभी seven hundred plants बन रहे हैं लेकिन आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा। देशभर के किसानों, self help groups, इन सबको इसमें जोड़ा जाएगा।

साथियो, आज गोबर-धन, वन-धन, जन-धन, इन योजनाओं से गरीबों, किसानों, आदिवासियों के जीवन में एक नई आर्थिक संभावनाएं, आर्थिक सामर्थ्य, एक नया बदलाव सुनिश्चित हो रहा है। न सिर्फ आपकी फसल, बल्कि पशु के गोबर का, खेत के अवशेष का, घर से निकले कूड़े-कचरे का, हर चीज का उचित उपयोग हो, इस दिशा में काम हो रहा है।

इसके अलावा जो जंगल में उगे पौधे और फल होते हैं, उनसे होने वाली आमदनी अलग। जब पतझड़ के मौसम में आप, अगर जंगलों में जाने की आदत होगी तो आपने देखा होगा- एक-एक, दो-दो फीट पत्ते गिर करके पड़े होते हैं। ये भी अपने-आपमें बहुत बड़ी कमाई का साधन बन सकता है। ये waste to wealth का अभियान है ही, साथ में इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी गति मिल रही है। क्योंकि यही waste गंदगी का भी बड़ा कारण है।

साथियो, इस अभियान में हमारे वैज्ञानिक बंधुओं और Start Up के जरिए तकनीक को सुलभ कराने वाले युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप बायोफ्यूल से जुड़ी तकनीक को बेहतर बनाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की संभावना है। जैसे अनाज के अतिरिक्त ऐसे उत्पादों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है जिससे अधिक गुणवत्ता वाला और अधिक मात्रा में बायोफ्यूल पैदा किया जा सके। इसके लिए Start Up से जुड़े उद्यमियों, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को एक साथ मिल करके काम करना होगा।

मैं समझता हूं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईटीआई पॉलिटेक्नीक के syllabus में बायोफ्यूल से जुड़े कोर्स को और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा देशभर के KVK's कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बायोफ्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। देशभर में लगने वाले कृषि मेलों में भी बायोफ्यूल को मुख्य थीम बनाकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।

साथियो, शहरों के साफ-सफाई से जुड़ी आभासबसे बड़ी समस्या यानि solid waste management- सीवर के पानी, उद्योग से निकला पानी, ऐसी तमाम चीजों से ऊर्जा पैदा करने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला ले करके खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था, कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है, और वहीं पर एक नाली-गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया। उसने उस नाली में- स्वाभाविक है जहां गंदी नाली होती है वहां गैस भी निकलता है- तो काफी दुर्गन्ध आती थी। उसने एक छोटे से बर्तन को उलटा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दिया और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइप लाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर-करके चाय बनाता था। सिम्पल सी टेक्नोलॉजी है। यानि कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का ये काम जरा ज्यादा रहता है।

एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि, हमारा conveyer जा रहा था और आगे स्कूटर पर बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है, पूरा अंदर भरा हुआ है, वो ले करके जा रहा था। कल्पना कर सकते हैं स्कूटर पर इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेकर जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता

है, कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा। आगे जा करके हवा भर देगा। वो ले जा रहा था, मैंने कहा जरा रोकिए इसको।

हमने गाड़ी रोकी और स्कूटर वाले को पूछा भाई क्या है ये, क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं- बोला खेत जा रहा हूं। मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो। तो बोला मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा-कचरा निकलता है वो, और मेरे पास दो पशु हैं उसका जो गोबर निकलता है तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा-सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब ले करके खेत जाता हूं। और खेत में जा करके उससे मेरा पानी का पम्प चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान। यानि इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं।

जो Start Up की दुनिया के लोग हैं, वे अगर उसपर ध्यान दें तो शायद जो कभी बड़े-बड़े collages से नहीं मिलता है वो खेत में किसान की सोच में से मिल सकता है। और इन सबको समेटकर हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

आज बी-3 की एक योजना, एक व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। बी-3 यानि बायोमास, बायोफ्यूल से और बायोएनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है। इथेनॉल के अतिरिक्त आज कचरे से सीएनजी यानि बायो-सीएनजी बनाने का भी तेज गति से काम चल रहा है। देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। फिलहाल हम सीएनजी विदेश से आयात करते हैं। अब बायो-सीएनजी से विदेशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक देश भर में पौने दो से अधिक प्लांट लगाए जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब शहरों के साथ-साथ गांवों में भी सीएनजी से गाड़ियां चलने लगेंगी।

साथियो, हमारे आसपास आज प्लास्टिक का सामान, रबर के टायर, ऐसी तमाम चीजें जो उपयोग के बाद एक अपने-आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं; इनका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा रहा है। और वहीं जो दूसरा कचरा- जो घर से निकला है- उसका भी सड़कों के निर्माण में कैसे उपयोग हो, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

मैंने अभी एक African countries की, गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मीडिया में देखा। वो गांव में से सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर-करके नदी के तट पर ले जाते हैं और लकड़ी-वकड़ी ला करके उस प्लास्टिक को जला करके पिघला लेते हैं। और वहीं नदी से बालू ले करके मिक्स करते हैं और उसमें से ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक बड़ीमात्रा में बेचते हैं वो। Women self help group की महिलाएं कर रही हैं ये काम। कचरे की सफाई भी कर रही हैं और उसका नया प्रॉडक्ट करके बाजार में बेच रही हैं।

विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर सरकार काम कर रही है। पर्यावरण के साथ संतुलन की जब हम बात करते हैं तब बिजली का एक महत्वपूर्ण रोल है। बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे इस्तेमाल होती है, इसका पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

जब बिजली पैदा करने की बात आती है तो आज कोयले और गैस जैसे पारम्परिक तरीकों के साथ सोलार एनर्जी समेत तमाम दूसरे माध्यमों से बिजली बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। International Solar Alliance के जरिए तो हम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

आज खेती में सोलर पंप से लेकर उद्योग धंधा, दफ्तरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर काफी प्रगति हो रही है। इसके अलावा देश की गलियों, घरों और दफ्तरों में एलईडी बल्ब की रोशनी सुनिश्चित करने से बिजली की बचत हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब देश के रेलवे स्टेशन एलईडी बल्ब से जगमगाने लगे हैं। सारा काम उन्होंने पूरा कर दिया। अब लक्ष्य ये है कि आने वाले दिनों में रेलवे की हर बिल्डिंग और रेलवे के हर क्वार्टर्स में भी शत-प्रतिशत एलईडी बल्ब लगाए जाएं। एलईडी लाइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण की चिंता- स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के मिशन से जुड़ी हुई है।

धुआमुक्त रसोई भी इसी व्यापक vision का हिस्सा है। आज मैं इस मंच से देश के उन पांच करोड़ गरीब परिवारों को बधाई देता हूं, उन माताओं-बहनों को बधाई देता हूं, जिनको धुए से मुक्ति मिली है।

हिन्दुस्तान में इतना बड़ा काम इतने समय में हो सकता है ये अपने-आप में अजूबा है। हमारे देश में सवा सौ करोड़ जनसंख्या है और करीब-करीब 25-26 करोड़ परिवार हैं। इन 25-26 करोड़ परिवार में 5 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा इतने कम समय में पहुंचाना, ये अपने-आप में, आप हिसाब लगा सकते हैं कि तेज गति से काम होता है तो कितना परिणाम आता है।

साथियों, आज दिनभर किसान भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, गर्वनमेंट के अफसर भी होंगे, आप सब मिल करके बायोफ्यूल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उससे जुड़ी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने वाले हैं। किसान की जो रोजमर्रा की practical problems हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि इसी सवा सौ करोड़ देशवासियों की ऊर्जा जरूरतों और खेती को लाभकारी बनाने के लिए अनेक नए सुझावस आएंगे, अनेक नए रास्ते बनेंगे।

बायोफ्यूल से बदलाव की क्रांति घर-घर सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि इसमें हमने हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे उद्यमियों को, यानि एक प्रकार से जन-भागीदारी से जन-आंदोलन का रूप हमको देना पड़ेगा।

मेरा यहां मौजूद जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि देश के गांव-गांव तक बायोफ्यूल के लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर भी अतिरिक्त प्रयास करें। और मुझे विश्वास है कि बायोफ्यूल की दिशा में भारत ने जो initiative लिए हैं और विश्व आज Biofuel day मना रहा है, तब भारत global warming से चिंतित विश्व को एक विश्वास देने का सामर्थ्य रखता है। भारत के इन कदमों की आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है।

भारत की नीतियों और योजनाओं को विश्व बड़े गौर से देख रहा है और उसमें आज का ये प्रयास नई ऊर्जा भरेगा, दिशा को और अधिक स्पष्ट करेगा और गति तेज करेगा। इसी विश्वास के साथ इस सफल योजना के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद।

अतुल तिवारी/शाहबाज हसीबी/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1543493) आगंतुक पटल : 268

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , Assamese , Tamil

प्रधानमंत्री कार्यालय

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा के उद्घाटन समारोह पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 02 OCT 2018 9:40PM by PIB Delhi

संयुक्त राष्ट्र के Secretary General, Excellency, Antonio Guterres, International Solar Alliance Assembly और Indian Ocean Rim Association, इन देशों से पधारे हुए सभी मंत्रीगण, केबिनेट के मेरे तमाम सहयोगी, उद्योग जगत के साथी, सम्मानीय अतिथिगण, विशेष रूप से नौजवान विद्यार्थी मित्र, देवियो और सज्जनों।

आज सुबह स्वच्छता से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में Excellency, Antonio Guterres के साथ मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला। आज से ही महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के आयोजन भी देश और दुनिया में प्रारंभ हो रहे हैं। Green future के लिए हो रहे इस मंथन की शुरुआत के लिए आज के दिवस से उचित अवसर कोई और नहीं हो सकता है।

International Solar Alliance (ISA), और मैं चाहूंगा कि popularly वो आईसा शब्द हो जाएगा यानी आईसा असेंबली हो। Global renewable energy investment and Expo and a Re-invest की बैठक हो या India Ocean Rim Association Energy Meet हो, तीनों का बृहद लक्ष्य एक है- Green future के लिए Clean energy का विकल्प तैयार करना।

साथियों, पिछले 150-200 वर्षों में मानव जाति अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए धरती के नीचे दबे संसाधनों पर ही ज्यादा निर्भर रही है। हमारी प्रकृति ने कैसे इसका विरोध किया है और आज भी कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। प्रकृति हमें लगातार संदेश दे रही है कि जमीन के ऊपर मौजूद ऊर्जा चाहे सूर्य में हो, वायु में हो या पानी में, यही बेहतर और सुरक्षित भविष्य का समाधान है।

मुझे खुशी है कि आज हम, हम सभी प्रकृति से मिल रहे इस संदेश पर मंथन के लिए एकजुट हुए हैं। साथियों, मुझे याद है तीन वर्ष पहले re-invest की पहली मीटिंग में मैंने renewable energy के क्षेत्र में मेगावाट से गीगावाट की तरफ भारत की यात्रा का संकल्प हमारे देशवासियों के सामने रखा था। तब मैंने ये स्पष्ट किया था कि Solar और green energy का लाभ तभी मिल पाएगा अगर ये सस्ती होगी और सुलभ होगी। और इसके लिए मैंने Solar resource rich countries का एक common platform बनाने का भी प्रस्ताव सामने रखा था। मुझे प्रसन्नता है कि हमें बहुत ही कम समय में इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है।

साथियों, आज International Solar Alliance दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। तीन वर्षों के भीतर ये संगठन एक treaty based inter governmental organization बन चुका है। सवा सौ करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि ISA का हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये ISA के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है।

मुझे लगता है जब भी भविष्य में 21वीं सदी में स्थापित मानव कल्याण के बड़े संगठनों की चर्चा होगी तो ISA का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। ISA के तौर पर हम सभी ने climate justice को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है। आने वाली पीढ़ियों को मानवता से जुड़ा बहुत बड़ा उपहार हम सबने मिल करके दिया है।

साथियो, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भूमिका आज OPEC निभा रहा है, वही भूमिका आने वाले समय में International Solar Alliance(आईसा) की होने वाली है। जो रोल आज तेल के कुंओं का है, वही रोल भविष्य में सूर्य की किरणों का होने वाला है। आज आईसा का ये initiative जहां पहुंचा है, इसमें सक्रिय सहयोग के लिए मैं United Nations का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं।

पेरिस में हुए ISA के launch कार्यक्रम में तब के महासचिव Excellency, Ban Ki-moon का मौजूद रहना और आज के कार्यक्रम में Excellency, Antonio Guterres का शामिल होना, ये इस बात को दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मंच को कितना महत्व देता है। मैं इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति का, उसकी सरकार का भी उनके सहयोग और समर्थन के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।

साथियो, ISA की इस पहली assembly में 40 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन अब हमें उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है जब सौर ऊर्जा के ये विकल्प सिर्फ Cancer और Capricorn के इर्द-गिर्द बसे सिर्फ सवा सौ देशों तक सीमित न रहें बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले। Universal cooperation on solar energy की भावना के तहत भारत ISA की assembly में यूनियन के सभी सदस्य देशों को membership का प्रस्ताव रखने वाला है।

साथियो, भारत India Ocean Rim Association का अहम सदस्य होने के नाते इस संगठन को बहुत महत्व देता है। हमारी ऊर्जा संबंधी चुनौतियां एक जैसी हैं। इसलिए अपनी energy security को देखते हुए renewable energy पर हमें मिलकर बल देना है।

मैं पहले भी SAGAR यानि security and growth for all in the region की भावना को सामने रख चुका हूं। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से सहयोग के नए द्वार खुलेंगे।

साथियो, renewable energy के बढ़ते उपयोग का भारत में असर दिखने लगा है। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए renewable energy की deployment के action plant पर काम हम शुरू कर चुके हैं। हमने तय किया है कि साल 2030 तक हमारी 40 प्रतिशत बिजली की क्षमता non fossil fuel based संसाधन से पैदा हो। इसी लक्ष्य के तहत बीते चार वर्षों में भारत ने renewable energy की अपनी क्षमता को 72 गीगावॉट यानी दोगुना किया है। इसमें भी solar energy की capacity में 9 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। आज जितनी बिजली का उत्पादन हम करते हैं उसका 20% हिस्सा non hydro renewable का है। इतना ही नहीं, करीब-करीब 50 गीगावॉट की क्षमता बहुत जल्द इसमें और जुड़ने वाली है। ये साफ संकेत है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट renewable energy उत्पादन का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है, उस रास्ते पर हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम करके रहेंगे।

साथियो, आज भारत poverty to power, इन नए आत्मविश्वास के साथ विकास की गति को तेज कर रहा है। इस नए आत्मविश्वास को शक्ति देने के लिए भी हमने उसको चुना है जो हजारों वर्षों से हमारी शक्ति का स्रोत रहा है, ऊर्जा का भंडार रहा है। ये भंडार है सूर्य का जिसको हम भारत के लोग सूर्यदेव के रूप में भी पूजा करते हैं।

साथियों, सूर्य हमारे लिए प्रकाश के देवता हैं, ऊर्जा के देवता हैं। हमारे यहां मान्यता है कि सूर्य सम्पूर्ण सृष्टि के गतिदाता हैं। ओम सूर्याय नमः के मंत्र से और सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देने से दिन की शुरुआत की हमारे यहां समाज जीवन में सहज परम्परा है। वेद से लेकर योग तक सूर्य हमारे चिंतन, हमारी उपासना, हमारी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत रहा है। अब इस आंतरिक ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान की शक्ति के साथ हम बाहरी ऊर्जा के समाधान में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं।

साथियों, Solar power के क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से काम कर रहा है। बीते चार वर्षों के दौरान Solar power बहुत सस्ती हुई है, जिससे अनेक गरीबों को बिजली से जोड़ने का हमारा लक्ष्य तेजी से संभव हो पाया है। घर-घर रोशनी पहुंचाने के हमारे लक्ष्य में panel to power और Make in India बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। मुझे खुशी है कि पिछले चार वर्षों में renewable energy के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा destination बनकर आज उभरा है। करीब 42 अरब का निवेश इस दौरान हुआ है।

साथियों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहे ये बदलाव सिर्फ विदेशी निवेश ही नहीं बल्कि हमारे अपने उद्यमियों के लिए भी एक अभूतपूर्व अवसर है। हमारी कोशिश है कि देश में ही Solar panel manufacturing का एक मजबूत eco system बने। Renewable energy के सेक्टर में निवेश का ये सबसे उपयुक्त समय है। आने वाले चार वर्षों में इस सेक्टर में करीब 70 से 80 अरब डॉलर के business की संभावनाएं मैं देख रहा हूं।

साथियों, power generation के साथ-साथ power storage भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी infrastructure तैयार करने के लिए National energy storage mission पर काम किया जा रहा है। इस मिशन के तहत सरकार demand creation, indigenous manufacturing, innovation और energy storage की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी policy support पर बल दे रही है।

KUSAM यानि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के माध्यम से गांव में खेत में ही Solar panel लगाने और उन्हें grid से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले चार वर्षों में देशभर में करीब 28 लाख solar pump लगाए जाने वाले हैं। इससे करीब 10 गीगावॉट की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

साथियों, Solar और wind power के साथ-साथ हम B-3 यानी biomass, bio fuel, bio energy पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। भारत में transport system को clean fuel based बनाने की तरफ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बायोगैस से बायो फ्यूल बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदल रहे हैं। हमने गोबरधन, एक बहुत बड़ी योजना इसके लिए प्रस्तुत की है। Waste to energy को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर में अनेक नवीन प्रयोग हो रहे हैं।

साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए renewable energy पर तो काम हो ही रहा है, बिजली की बचत हो ये भी हमारी प्राथमिकताओं में से है। उजाला स्कीम के तहत देश के घरों, गलियों और सड़कों को LED bulb से रोशन करने का सबसे बड़ा अभियान आज भारत के हर कोने में चल रहा है। इसके तहत अब तक करीब 31 करोड़ LED bulb बांटे गए हैं। ये 31 करोड़ LED bulb बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जिससे हर वर्ष करीब 40 हजार मिलियन किलोवॉट आवर बिजली की बचत हो रही है। कोई कल्पना कर सकता है कितना बड़ा है। इतना ही नहीं इससे देशवासियों का बिजली के बिल में हर वर्ष करीब-करीब 16 हजार करोड़ रुपयों की बचत हुई है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड के generation को हमने रोका है।

और फिर मैं कहना चाहूंगा, ये तो अभी शुरूआत ही है। आने वाला समय और अनेक अवसरों से भरा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें climate justice से जुड़े हर अवसर की संभावनाओं को तलाशना है और सफलता प्राप्त करके ही रहना है।

मुझे विश्वास है कि आने वाले तीन दिनों में इन अवसरों पर विस्तार से आप सभी महानुभाव चर्चा करेंगे और renewable future को और प्रकाशित, प्रसाधित करने में योगदान देंगे।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका हर सुझाव, हर innovative idea हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए अब खुल करके Human Resource Development हो, technology up gradation हो, नए-नए दुनिया के देशों में छोटे-छोटे लोगों ने प्रयोग किए हों, इन सारी बातों को हम एक बार सामने लाएंगे और मुझे विश्वास है कि हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। और हम दुनिया के सामने आर्थिक जगत की दुनिया में globalization की चर्चा हुई, technology ने दुनिया को बहुत निकट ला दिया। हम भी एक dream ले करके चले कि एक दुनिया, एक सूरज, एक grid. One World, One Sun, One Grid.

अगर इस मिशन को पार करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां सूर्योदय होता है, वहां से चालू करें तो सूर्यास्त तक ये Grid बनी रहे तो चौबीसों घंटे सूरज से बिजली निकल सकती है। आज तो हमारे देश में जितने घंटे सूरज है उसी की हम सोचते हैं लेकिन One World, One Sun, One Grid, इस सपने को ले करके हम चलेंगे तो कभी भी, कहीं पर भी जब तक सूरज ढलता नहीं है, बिजली पाना असंभव नहीं होगा और सूरज कहीं न कहीं तो होता ही है, कभी ढलता नहीं है तो फिर बिजली का प्रवाह क्यों बंद होगा।

एक नए तरीके से, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि ISA के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हम जरूर एक नए विश्वास के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ, एक नए विश्व के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे।

एक बार फिर भारत आने के लिए, यहां आ करके इस महत्वपूर्ण अवसर पर शरीक होने के लिए मैं दुनिया के उज्ज्वल भविष्य में अपनी सहभागिता के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1550113) आगंतुक पटल : 339

प्रधानमंत्री कार्यालय

9वें सीजीडी बोली-प्रक्रिया दौर के तहत सिटी गैस वितरण परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 22 NOV 2018 7:56PM by PIB Delhi

मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेन्द्र प्रधान जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज के Bidding process में शामिल हो रहे उद्यमीगण और यहां उपस्थित सभी महानुभाव।

भाइयों और बहनों, भविष्य के भारत के लिए किस तरह आजकल भारत में बड़े संकल्प लेकर कार्य को सिद्ध किया जा रहा है, आज हम सभी उसके गवाह बने हैं। आज का दिन भारत में next generation infrastructure, उसे विकसित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 9वें Bidding Round से देश के 129 districts में City Gas Distribution network स्थापित करने के कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा 10वीं Bidding का process भी शुरू हुआ है।

ये शुरुआत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये कार्य पूरे होंगे तो उसका परिणाम बहुत ही व्यापक होगा, बृहद होगा। 10वीं Bidding के बाद शुरू हुए कार्य जब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे तो देश के 400 से ज्यादा जिले City Gas Distribution network के दायरे में आ जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि देश की करीब-करीब 70 प्रतिशत आबादी को ये सुविधा मिलने का मार्ग खुल जाएगा। देश के विकास से जुड़ी, देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने से जुड़ी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

साथियों, 2014 तक देश के सिर्फ sixty six districts, 66 जिले यहां पर City Gas Distribution network के दायरे में, वहां तक पहुंचा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के 174, जिलों में City Gas का काम चल रहा है। अगले दो-तीन वर्षों में 400 से ज्यादा जिलों तक इसकी पहुंच होगी।

ये कोई छोटे-मोटे आंकड़े नहीं हैं जी। हमारे शहरों ने बीते चार वर्षों में Gas based Economy की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, ये उसकी भव्य तस्वीर है। 2014 में लगभग 25 लाख घरों में Piped Gas Connection था। चार साल में इसकी संख्या बढ़ करके लगभग दो गुनी हो चुकी है। आज जिन शहरों में कार्यों की शुरुआत हुई है उसके बाद ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह 2014 में देश में 947 CNG station थे। मत भूलिए, कि आज से लगभग 25 साल पहले देश के तीन शहर दिल्ली, मुम्बई और सूरत, जहां पर पहले सीएनजी स्टेशन खुले थे। तब से लेकर 2014 तक इनकी संख्या 947 तक पहुंची थी। यानी मोटे तौर पर अगर हम औसत निकालें तो कह सकते हैं कि एक साल में करीब-करीब 40 सीएनजी स्टेशन खुले, इतने सालों में, हर वर्ष चालीस। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 1470 से ज्यादा हो चुकी है। अनुमान ये भी है कि इनकी आने वाले दशक के अंत तक सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़कर 10 हजार के पार होने की पूरी व्यवस्था है।

भाइयो, बहनों, केंद्र सरकार के चार वर्षों के अथक प्रयास के बाद अब देश इस स्थिति में आ गया है कि वह City Gas Distribution network के विकास में पहले की अपेक्षा आज कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के विकास में आने वाली रुकावटें, silos, Distributors को आने वाली परेशानी, हमने

हर चुनौती को एक-एक कर दूर करने का प्रयास किया है।

मैं जिस reform, perform, transform के मंत्र की बात करता हूँ, उसका ये सेक्टर बहुत ही उत्तम उदाहरण है। सरकार ने बीते चार वर्षों में जो कदम उठाए, जो reforms किए, उसने इस सेक्टर की performance बढ़ा दी है और हम transform के दौर में प्रवेश करने वाले हैं।

साथियों, 2022, हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक भव्य भारत, एक नए भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त और पुरानी पड़ चुकी व्यवस्थाओं से मुक्त हो। इसी vision के साथ देश के energy sector का कायाकल्प किया जा रहा है।

ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश में बढ़ रही economy activities ने energy की demand बहुत बढ़ा दी है। ऊर्जा की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के साथ ही हमें clean energy के हमारे commitment का भी ध्यान रखना है। हमें दुनिया को ये भी दिखाना है कि पर्यावरण को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए भी विकास हो सकता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए natural gas का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है।

हमारा प्रयास है कि अगले दशक के अंत तक देश में natural gas की खपत को ढाई गुना से ज्यादा बढ़ाया जाए। और इसलिए सरकार Gas Based Economy के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में gas infrastructure को मजबूत करने के लिए LNG Terminals की संख्या बढ़ाने, Nationwide Gas Grid और City Gas Distribution पर एक साथ काम किया जा रहा है। Liquid natural gas के import की क्षमता बढ़ाने के लिए पुराने टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण हो ही रहा है, नए LNG Terminal भी बनाए जा रहे हैं।

10 हजार करोड़ की लागत राशि से तमिलनाडु के एन्नौर और उड़ीसा के धामरा में नए LNG Terminals का काम आखिरी चरण में है। इसी तरह देश के ज्यादा से ज्यादा जिलों तक नेचुरल गैस पहुंच सके, इसके लिए national gas grid का eco system विकसित किया जा रहा है।

इसके तहत जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो- धामरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। साथ ही उत्तर-पूर्व के दूसरे क्षेत्रों को इस गैस-ग्रिड से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार बरौनी से गुवाहाटी तक किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन परियोजनाओं की वजह से गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक नया जीवनदान मिलने जा रहा है। सिक्किम समेत नॉर्थ-ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 crore से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड के नाम से एक joint venture भी बनाया गया है।

साथियों, जो निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा गया है। घरेलू गैस की कीमतों को ग्लोबल गैस मार्केट से लिंक करने का काम पहले ही किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम्पनियों को marketing और pricing freedom दे दी गई है।

गैस की कीमतों पर ध्यान देने के लिए, गैस ग्रिड के संचालन के लिए, एक independent transport system operator भी बनाया गया है। इसके साथ ही देश में फ्री गैस मार्केट का वातावरण बनाने, इस सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार Gas trading exchange को विकसित करने पर भी काम कर रही है।

भाइयो और बहनों, इन तकनीकी पहलुओं और आंकड़ों के साथ ही हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन कार्यों, इन परियोजनाओं का देश पर सकारात्मक प्रभाव। ये कार्य सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।

साथियों, जब किसी भी जगह कोई नई व्यवस्था का निर्माण होता है तो उसकी वजह से आसपास के बड़े इलाके में eco system का भी निर्माण हो जाता है। जैसे किसी जगह पर कोई बड़ा अस्पताल खुलता है तो उसके आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, चाय की दुकान होगी, धर्मशालाएं होंगी, छोटे-छोटे होटल खुल जाएंगे, ऑटो स्टैंड बन जाएगा, टैक्सी स्टैंड बन जाएगा; ये सभी अपने-अपने तरीके से काम करते हैं लेकिन उनके अस्तित्व के केन्द्र में वो अस्पताल होता है।

इसी तरह जब किसी शहर में गैस पहुंचती है तो वो भी एक नए eco system का निर्माण करती है। उस शहर में गैस आधारित छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना कई गुना बढ़ जाती है। पाइप के जरिए सीधे लोगों के घरों में पहुंचाने वाली गैस लोगों के जीवन ease of living को और आसान बनाती है। उस पाइप को बिछाने के लिए, सीएनजी या पीएनजी नेटवर्क को साबित करने के लिए हजारों-लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। उस शहर में चलने वाले ऑटो, टैक्सियों, कारों को ईंधन का एक आधुनिक विकल्प मिलता है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजनाएं अभी देश में चल रही हैं, उनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

आज नवीं बीडिंग के तहत जो कार्य शुरू हुए हैं, उससे ही सीधे तौर पर कम से कम तीन लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्थाएं विकसित होंगी वो भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनाएंगी। खासतौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये कि Gas Based व्यवस्थाएं सिर्फ उद्योगों को ही नहीं, उस जिले के लोगों का रहने का तौर-तरीका भी बदल रही हैं। उनकी जीवन पद्धति बदल रही है।

आने वाले कुछ एक वर्षों में भारत के सैंकड़ों शहरों में, इस बदलाव को खुद होते हुए देखेंगे और आप भी उसके सहभागी बनेंगे। हम खुद को इस मामले में सौभाग्यशाली भी महसूस कर सकते हैं कि हम अपने जीवनकाल में इतने बड़े परिवर्तन को होते हुए देख रहे हैं, वरना मुझे वो दौर भी याद है जब देश के आम नागरिक अपने घर में गैस का सामान्य कनेक्शन लेने के लिए सांसदों, विधायकों तक की सिफारशी चिट्ठी लिखाने के लिए कतार में खड़ा रहता था। उस स्थिति से देश बहुत आगे निकल चुका है।

अगर मैं कहूं कि साल 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि सरकार की कार्य शैली, कार्य संस्कृति और योजनाओं को लागू करने का तौर-तरीका भी बदल दिया है तो गलत नहीं होगा। आज इस अवसर में आपको इसी सैंक्टर से जुड़ा एक और उदाहरण देता हूं। हम लोग Gas Based Economy की बात करते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाना 1955 में शुरू हुआ था। इसके बाद से 2014 तक देश में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। यानी 60 साल में 13 करोड़ कनेक्शन। ये आंकड़े अगर आप याद रखोगे तो लोगों से बात करे समय आप विश्वास से कह सकोगे कि कैसे बदलाव आ रहा है, 60 साल में 13 करोड़। देश में सारे संसाधन वही हैं, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, दफ्तर वही हैं, बाबू का काम करने का तरीका भी वही है, फिर भी चार साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

60 साल में 13 करोड़, चार साल में 12 करोड़, अगर उस गति से चलते तो शायद हमारी दो पीढ़ी के बाद भी ये लाभ परिवार को नहीं मिलता। घरेलू गैस कवरेज का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55 प्रतिशत था, अब बढ़कर लगभग 90 प्रतिशत हो गया है। निश्चित तौर पर इसमें उज्ज्वला योजना की

बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1 मई, 2016 को शुरू होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। इस योजना ने देश के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन जीने का तरीका बदल दिया है।

ये बीडिंग के प्रोसेस के बीच, शिलान्यास के बीच, आज पलभर के लिए हमें उस महिला के बारे में भी सोचना चाहिए जो अब तक लकड़ी का चूल्हा फूंक रही थी। अपनी सेहत को दांव पर लगाकर परिवार का पेट भर रही थी। इस महिला को Gas Based Economy का मतलब भले न पता हो, लेकिन Gas Based Economy की तरफ बढ़ते देश के कदमों ने उसका जीवन जरूर बदल दिया है।

भाइयों और बहनों, कुछ देर पहले मैंने आपसे पर्यावरण की बात की थी। जिस Gas Based Economy की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा और बेहतर प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला है। जब देश में हजारों नए सीएनजी स्टेशन होंगे, उद्योगों को बिना रुकावट गैस मिलेगी, टैक्सियों, ऑटो, कारों में भरने के लिए देश के ज्यादातर जिलों में सीएनजी आसानी से उपलब्ध होगी, तो प्रदूषण भी उतना ही कम होगा। ये COP21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी और मजबूत करेगा। ये वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के योगदान को मजबूत करेगा। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के नेतृत्व की चमक को और बढ़ाएगा।

साथियों, clean energy के लिए सरकार के प्रयास का विस्तार बहुत व्यापक है। हमारी कृषि व्यवस्था से जो waste निकलता है, Biomass निकलता है, उसे Compressed Bio Gas बनाने की दिशा में भी एक अभियान सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत आने वाले पांच सालों में देश में पांच हजार Compressed Bio Gas plants की स्थापना की जाएगी।

ये प्लांट पराली जलाने, एग्री वेस्ट जैसी समस्याओं को कम तो करेंगे ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होंगे। इसके अलावा biomass को bio fuel में बदलने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 12 आधुनिक bio refinery बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। Ethanol blending को लेकर सरकार ने जो नीतिगत परिवर्तन किए हैं, उससे Ethanol blending में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

2014 में जहां देश में लगभग 40 करोड़ लीटर Ethanol की blending होती थी, वो अब लगभग चार गुना तक बढ़ चुकी है। सरकार का लक्ष्य अब Ethanol की blending को 10 प्रतिशत तक ले जाने का है। आने वाले वर्ष में Ethanol blending साल 2014 के मुकाबले लगभग आठ गुना हो जाएगी।

Clean energy से clean environment की दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने BS-4 ईंधन से सीधा BS-6 ईंधन पर जाने का भी फैसला किया है। टेलीकॉम में हम 2जी से 4जी, 4जी से 5जी, हम यहां से सीधे चार से छह गए हैं। इसके अलावा एलईडी बल्ब की कीमतों में आई कमी और देश के लगभग 32 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण ने भी तीन करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का emission रोकने में मदद की है।

सरकार twenty-twenty two तक, 2022 तक देश में renewable energy से 175 Giga watt ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके तहत कम से कम 100 Giga watt बिजली सोलर एनर्जी से बनाई जाएगी। आने वाले चार वर्षों में सरकार किसानों को 28 लाख से ज्यादा सोलर पंप बांटने का अभियान भी चलाया जा रहा है। देश में गैस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही ये सारे प्रयास भारत के global commitment को पूरा करने में मदद करेंगे।

एक तो ये कि भारत 2030 तक अपनी emission intensity को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करेगा और दूसरा कम से कम 40 प्रतिशत बिजली की जरूरत गैर पारम्परिक स्रोतों से पूरा करेगा।

भाइयो, बहनों, गैस बेस्ड इकोनॉमी से जुड़े लक्ष्यहो को या फिर क्लीन एनर्जी से, ये लक्ष्य भारत को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम करके रहेंगे। सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमने ये संकल्प लिया है और उसे सिद्ध करना हमारा सबका दायित्व है।

मैं एक बार फिर आप सभी को, जिन शहरों में City Gas Distribution Network का काम शुरू हो रहा है वहां के लोगों को, 10वीं बीडिंग से जुड़े प्रतिनिधियों को अनेक-अनेक शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/कंचन पतियाल/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1553631) आगंतुक पटल : 348